

महंगी मशीनें विलासिता नहीं बुनियादी जरूरत

गाल बजाते राजनेता और लोक कल्याणकारी होने का दावा करती सरकारों की नाक के नीचे सरकारी अस्पतालों की कैसी बढहाली है, ये किसी से नहीं छिपा है। लोकलुभावन कार्यक्रमों पर पैसा पानी की तरह बहाने वाली सरकारों व मंत्रियों की प्राथमिकताओं में, वे सरकारी अस्पताल कभी नहीं रहे हैं, जो गरीबों व साधनविहीन लोगों का अंतिम आश्रय होते हैं। कायदे से तो सरकारों को इस मुद्दे को प्राथमिकता मानते हुए तत्काल प्रभाव से अस्पतालों की दशा सुधारनी चाहिए। लेकिन विडंबना है कि हर बार न्यायालय को ही जनहित से जुड़े मुद्दों पर सख्ती दिखाकर सरकारों को कार्रवाई करने को कहा जाता है। एक बार फिर पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश से पंजाब तथा हरियाणा सरकारों की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के संचालकों को एक बेहद जरूरी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने दोनों राज्यों को निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक जिला अस्पताल में आईसीयू सुविधाओं के साथ-साथ सीटी स्कैन और एमआरआई मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। निश्चित रूप से न्यायालय के इस तरह के सकारात्मक हस्तक्षेप से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सताधीशों के वायदों और उनके क्रियान्वयन के बीच बढ़ती खाई ही उजागर होती है। वहीं अदालत की कार्यवाही के दौरान पंजाब सरकार की ओर से न्यायालय को सूचित किया गया कि राज्य के 23 जिलों में से केवल छह जिला अस्पतालों में ही एमआरआई की सुविधा उपलब्ध है। दूसरी ओर राज्य के अस्पतालों में दो हजार से अधिक जनरल मेडिकल ऑफिसरों के पद और अन्य सैकड़ों विशेषज्ञों के पद खाली पड़े हुए हैं। वहीं कई जिलों के सरकारी अस्पतालों में कार्यशील आईसीयू की कमी है। अदालत ने हरियाणा सरकार से भी गहन देखभाल व निदान सुविधाओं की कमियों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। निस्संदेह, इन खामियों से फिर उजागर हुआ है कि अनेक सरकारी अस्पतालों में महंगे चिकित्सा उपकरण अक्सर बिना इस्तेमाल के या कम उपयोग में क्यों रहते हैं। वहीं दूसरी ओर विभागे के उच्च अधिकारियों द्वारा भी गरीब व जरूरतमंद मरीजों की तात्कालिक जरूरतों को अनदेखा ही किया जाता है।

न्यायालय की इस बात से बिल्कुल सहमत हुआ जा सकता है कि मौजूदा दौर में सीटी स्कैन, एमआरआई और आईसीयू तक मरीजों की पहुंच विलासिता नहीं, बल्कि बुनियादी स्वास्थ्य सेवा की आवश्यकता बन गई है। जो इस बात पर भी बल देता है कि सरकारें जिला स्तरीय क्रियाशील बुनियादी ढांचा बनाने के बजाय अनिश्चित काल तक आउटसोर्सिंग या रेफरल प्रणालियों पर निर्भर नहीं रह सकती हैं। वास्तव में सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली केवल खरीदी की कमी से ही नहीं, बल्कि बिना योजना के भारी-भरकम खरीदी की प्रवृत्ति से भी प्रस्त है। वहीं दूसरी ओर अक्सर तकनीशियनों की अनुपलब्धता से एमआरआई मशीनें स्थापित नहीं हो पाती हैं। वहीं अनुबंध समाप्त होने के कारण अक्सर वेंटिलेटर धूल खाते रहते हैं। दूसरी तरफ रेडियोलॉजिस्ट और बायोमेडिकल इंजीनियरों की अनुपस्थिति के कारण निदान सेवाओं को आउटसोर्स किया जाता है। बार-बार की गई ऑर्डर रिपोर्टों से पता चलता है कि सरकारी अस्पतालों में करोड़ों रुपये के जीवन रक्षक उपकरण महीनों से लेकर वर्षों तक बेकार ही पड़े रहते हैं। जिसका खमियाजा जरूरतमंद मरीजों को उठाना पड़ता है। किसी भी अस्पताल में एक खराब सीटी स्कैनर की वजह से दुर्घटना पीड़ितों, कैंसर के मरीजों और हृदयाघात के रोगियों के उपचार में देरी होती है। दूसरी ओर सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों का हर एक खाली पद कमजोर वर्ग के लोगों को महंगे निजी अस्पतालों में उपचार के लिये धकेल देता है। यह विडंबना ही है कि दूर-दराज के ग्रामीण इलाकों के मरीज अक्सर लंबी दूरी तय करके सरकारी अस्पतालों तक पहुंचते हैं। अक्सर देखा जाता है कि उन्हें या तो मशीनें काम न करने वाली मिलती हैं या चलाने वाले कर्मचारी नहीं मिलते। निर्विवाद रूप से केवल मशीनें लगाने से ही मरीजों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता। सही मायनों में सरकारी अस्पतालों में उपकरणों की उपलब्धता के साथ ही डॉक्टरों, तकनीशियनों आदि की जवाबदेही भी सुनिश्चित होनी ही चाहिए। वास्तव में किसी भी स्वास्थ्य सेवा का मूल्यांकन खरीदी गई महंगी मशीनों से नहीं, बल्कि सही समय पर उपचार का लाभ पाने वाले मरीजों की संख्या से होता है।

आज का पंचांग

कोलकाता : 22 मई, शुक्रवार, 2026, विक्रम सम्वत् 2083, ज्येष्ठ शुक्लपक्ष षष्ठी, 06:25 तक, नक्षत्र : आश्लेषा, 26:07 तक, योग : वृद्धि, 08:17 तक, श्योदश: 04:54, सूर्यास्त: 18:12, चन्द्रोदय : 10:59, चन्द्रास्त: 24:19, राक सम्वत: 1948 पराभव, सूर्य राशि : वृषभ, चन्द्र राशि : कर्क, राहू काल : 10:32 से 12:10

राशिफल

मेघ : आज का दिन आपके लिए नई उम्मीदों और बड़ी राहत का संदेश लेकर आया है। लंबे समय से अटका कोई काम आखिरकार पूरा हो सकता है, जिससे मन हल्का महसूस होगा।
वृष : आज कुछ खास लोगों से मुलाकात आपके करियर और बिजनेस के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हालांकि किसी दूर के रिश्तेदार से मिली खबर थोड़ी चिंता बढ़ा सकती है।
मिथुन : आज आपकी सुझबुझ और फैसले लेने की क्षमता आपको दूसरों से आगे रखेगी। विरोधियों की बातों में आकर कोई गलती करने से बचें। घर में शादी-विवाह की चर्चा भी जोर पकड़ सकती है।
कर्क : आज वैवाहिक जीवन में प्यार और समझदारी का सुंदर संतुलन देखने को मिलेगा। माताजी से किया गया वादा पूरा करने का अवसर मिलेगा। कोई सूचना दिन को और खास बना सकती है।
सिंह : आज का दिन खुशियों और उपलब्धियों से भरा रहेगा। कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए नए रास्ते खोल सकती है। परिवार के साथ बिताया गया समय रिश्तों में और मजबूती लाएगा।
कन्या : आज आर्थिक मामलों में किस्मत आपका पूरा साथ दे सकती है। पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के योग हैं और आय बढ़ने से मन प्रसन्न रहेगा। सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा।
तुला : आज का दिन काफी भागदौड़ और व्यस्तता से भरा रह सकता है। अपने काम खूद करने की कोशिश करें और दूसरों पर ज्यादा निर्भर न रहें। पुराने मित्र से मुलाकात दिल को खुश करे देगी।
वृश्चिक : आज सेहत में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है, इसलिए खान-पान पर विशेष ध्यान दें। अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। रक्त संबंधों में मजबूती आएगी।
धनु : आज मन की कोई इच्छा अधूरी रहने से थोड़ी बेचैनी महसूस हो सकती है। काम में मन कम लगेगा, इसलिए खूद को सकारात्मक रखने की कोशिश करें।
मकर : आज अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। बिजनेस में अच्छा मुनाफा मिलने से मन प्रसन्न रहेगा और पुराना अटका पैसा भी वापस मिल सकता है। सहयोगी की बात दिल को चुभ सकती है।
कुम्भ : आज का दिन सामान्य से बेहतर साबित हो सकता है। अचानक यात्रा के योग बन रहे हैं। संतान यदि किसी परीक्षा में शामिल हुई थी तो उसका परिणाम खुशी दे सकता है।
मीन : आज बिजनेस में उतार-चढ़ाव के कारण मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। पार्टनरशिप में संतर्क रहना जरूरी होगा, क्योंकि धोखे की संभावना बन रही है।

राजनीति सनातन विरोध की बजाय आममुद्दों पर केंद्रित हो



ललित गर्ग

सामाजिक न्याय जैसे मूल प्रश्नों से हटाकर धार्मिक पहचान और आस्था के इर्द-गिर्द खड़ा कर दिया है। यह विमर्श है-सनातन समर्थन बनाम सनातन विरोध। आज देश में एक ओर सनातन संस्कृति को भारतीय जीवन का शाश्वत आधार मानने वाली शक्तियां हैं, तो दूसरी ओर कुछ राजनीतिक वक्तव्य और प्रवृत्तियां ऐसी दिखती हैं जिन्हें जनमानस सनातन विरोध के रूप में देखता है। प्रश्न यह नहीं कि किसी विचारधारा से सहमति या असहमति क्यों है, बल्कि प्रश्न यह है कि क्या राजनीति का केंद्र धर्म होना चाहिए या जनजीवन के वास्तविक मुद्दे? भारत का लोकतंत्र धर्मनिरपेक्ष संविधान पर आधारित है, जहां राज्य का कार्य किसी धर्म का पक्ष या विरोध नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है। राजनीतिक दलों का दायित्व भी यही होना चाहिए कि वे जनता की समस्याओं, विकास और राष्ट्रीय एकता को प्राथमिकता दें। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक विमर्श राजनीति का बड़ा केंद्र बन गया है। सनातन केवल एक धार्मिक शब्द नहीं, बल्कि भारतीय सभ्यता की सांस्कृतिक चेतना, जीवन-दर्शन और मूल्य परंपरा का प्रतीक है। स्वयं वद, धर्म चर, वसुधैव कुटुम्बकम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे सूत्र इसी सनातन दृष्टि के अंग हैं। इसलिए जब कोई राजनीतिक वक्तव्य सनातन को लेकर अपमानजनक या आक्रामक भाषा का

उपयोग करता है, तो उसका प्रभाव केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और भावनात्मक स्तर पर भी पड़ता है। तमिलनाडु में द्रमुक नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म की तुलना बीमारी से करने वाला वक्तव्य इसी कारण व्यापक विवाद का कारण बना। विपक्ष के अनेक दलों ने उससे दूरी बनाने का प्रयास किया, क्योंकि यह स्पष्ट था कि भारत जैसे देश में करोड़ों लोगों की आस्था को आहत करने वाला कथन राजनीतिक रूप से भी असहज स्थिति उत्पन्न करेगा। यहां यह समझना आवश्यक है कि द्रविड आंदोलन की अपनी ऐतिहासिक और सामाजिक पृष्ठभूमि रही है। उसका मूल संघर्ष सामाजिक विषमताओं और जातीय वर्चस्व के विरुद्ध था। लेकिन जब सामाजिक सुधार का विमर्श धर्म या संस्कृति के विरोध जैसा प्रतीत होने लगे, तब वह जनस्वीकृति खो देता है। यह भी सत्य है कि अनेक विपक्षी दल स्वयं को सनातन विरोधी नहीं, बल्कि सामाजिक कुरीतियों, जातिवाद और भेदभाव के विरोधी बताते हैं। उनका तर्क है कि वे सामाजिक न्याय और संवैधानिक मूल्यों की बात करते हैं। यह दृष्टि लोकतंत्र में स्वीकार्य है, क्योंकि हर परंपरा में आत्मसमीक्षा और सही धर्म की आवश्यकता होती है। स्वयं भारतीय दर्शन में भी संवाद, बहस और आत्मचिंतन की परंपरा रही है। बुद्ध, महावीर, कबीर, नानक, दयानंद और गांधी-सर्वे में समाज की विसंगतियों पर प्रश्न उठाए, लेकिन उन्होंने समाज को तोड़ने नहीं, सुधारने का मार्ग चुना। समस्या तब उत्पन्न होती है जब राजनीतिक भाषा संतुलन खो देती है। जब आलोचना सुधार की जगह अस्वीकार की भाषा बन जाती है, तब वह समाज में ध्रुवीकरण को जन्म देती है। भारत जैसे बहुलतावादी देश में यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं कही जा सकती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले

एक दशक में भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का विमर्श अधिक प्रभावी होकर उभरा है। राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक, सांस्कृतिक धरोहरों के पुनरुत्थान जैसे विषयों ने एक बड़े वर्ग में सांस्कृतिक आत्मविश्वास को मजबूत किया है। इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक लाभ भी मिला। दूसरी ओर विपक्षी दल इस बदलते राजनीतिक मानस को समझने में कई बार असहज दिखाई दिए। कहीं उन्होंने धर्मनिरपेक्षता और आस्था के बीच संतुलन बनाने में चूक की, तो कहीं उनके कुछ नेत-1ओं के बयान उन्हें कठिन स्थिति में ले आए। उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक चुनावी राजनीति में यह देखा गया कि केवल जातीय समीकरण या पारंपरिक वोट बैंक अब पर्याप्त नहीं हैं। जनता सांस्कृतिक पहचान, विकास और राष्ट्रीय विमर्श को भी महत्व देने लगी है। ऐसे में यदि कोई दल हिंदू आस्था के प्रति असंवेदनशील दिखता है, तो उसका राजनीतिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे विमर्श का दूसरा पक्ष भी है। क्या राजनीति का उद्देश्य केवल धार्मिक पहचान के आधार पर समर्थन जुटाना होना चाहिए? क्या देश के सामने मौजूद बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, कृषि संकट, आर्थिक असमानता और सामाजिक विघटन जैसे प्रश्न पीछे छूट जाने चाहिए? यह चिंता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। भारतीय राजनीति में पिछले कुछ वर्षों के दौरान धर्म, विशेषकर सनातन और हिंदू आस्था को लेकर कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल कांग्रेस, द्रमुक आदि विपक्षी दलों एवं उनके कुछ नेताओं द्वारा दिए गए बयानों को व्यापक जनसमुदाय ने सनातन पर आक्षेप जैसे बहुलतावादी देश में यह प्रवृत्ति लोकतांत्रिक स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं कही जा सकती।

में देखना पर्याप्त नहीं होगा। भारत एक लोकतांत्रिक और बहुलतावादी राष्ट्र है, जहां किसी भी राजनीतिक दल को सरकार, अधिकार है, लेकिन यदि वह विरोध आस्था, संस्कृति और बहुसंख्यक समाज की भावनाओं से टकराता हुआ प्रतीत हो, तो उसका राजनीतिक मूल्य चुकाना पड़ सकता है। यही कारण है कि कई दलों के लिए यह धारणा चुनौती बनी कि वे सत्ता-विरोध की राजनीति करते-करते सांस्कृतिक और धार्मिक संवेदनाओं से दूर हो गए हैं। भारत में सनातन केवल धार्मिक पहचान नहीं, बल्कि जीवन-दर्शन, परंपरा, संस्कृति, सहिष्णुता और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है, इसलिए उसके प्रति असावधान भाषा या नकारात्मक संकेत जनमानस में प्रतिकूल प्रतिक्रिया उत्पन्न करते रहे हैं। दूसरी ओर लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा यह भी अपेक्षा करती है कि राजनीतिक विमर्श व्यक्तियों, नीतियों और शासन के मुद्दों पर केंद्रित रहे, न कि धार्मिक ध्रुवीकरण पर। राजनीतिक दलों के लिए यह आवश्यक है कि वे मतभेद रखें, आलोचना करें, लेकिन भारतीय समाज की सांस्कृतिक चेतना, धार्मिक संवेदनाशीलता और आस्था के सम्मान का संतुलन बनाए रखें, क्योंकि जनता अंततः उसी नेतृत्व को स्वीकार करती है जो उसकी भावनाओं, परंपराओं और राष्ट्रीय मानस को समझने का प्रयास करता है। भारत की राजनीति को धर्म बनाम धर्म की लड़ाई से ऊपर उठकर जन बनाम जनसमस्या के विमर्श की ओर बढ़ना होगा। राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि जनता मंदिर भी चाहती है और रोजगार भी, आस्था भी चाहती है और अवसर भी, संस्कृति भी चाहती है और आधुनिकता भी। केवल धार्मिक ध्रुवीकरण किसी राष्ट्र की स्थायी प्रगति का आधार नहीं बन सकता। आज आवश्यकता है कि राजनीतिक दल सनातन विरोध या हिंदू विरोध जैसे आरोप-

सुप्रीम कोर्ट का आवश्यक हस्तक्षेप



रोहित माहेश्वरी

देश में आवाज के कुत्तों के हमलों और काटने की बढ़ती घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अधिकारियों को उन पागल, गंभीर रूप से बीमार और भूखे आवाज कुत्तों को कानूनी रूप से इच्छा मृत्यु देने का निर्देश दिया है जो मानव जीवन के लिए खतरा बन चुके हैं। जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस सदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने पशु प्रेमियों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा दायित्व याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया। अदालत ने पिछले साल नवंबर में दिए गए अपने उस आदेश में संशोधन करने से इनकार कर दिया, जिसमें आवाज कुत्तों को शेल्टर होम में स्थानांतरित करने की बात कही गई थी। पिछले साल जुलाई में रेबीज के कारण एक हज़ार की बच्ची की मौत की खबर के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान में लिया था, जिसके बाद लंबी सुनवाई के बाद यह ऐतिहासिक फैसला आया है।

फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा, गरिमा के साथ जीने के अधिकार में यह अधिकार भी शामिल है कि व्यक्ति कुत्तों के हमलों के डर के बिना स्वतंत्र रूप से जीवित जी सके। राज्य मुकदमों के बने रह सकते हैं। अदालत भी उन कठोर जमीनी हकीकतों से आंखें नहीं मूंद सकती, जहां बच्चे, विदेशी यात्री और बुजुर्ग कुत्तों के काटे की घटनाओं का शिकार हुए हैं। संविधान ऐसे समाज की कल्पना नहीं करता, जहां बच्चे और बुजुर्गों का जीवन केवल शांतिरहित ताकत या किस्मत के भरोसे हो। इसमें दो राय नहीं कि स्थानीय

निकायों द्वारा आवाज कुत्तों को हटाने के संबंध में विगत में दिए अपने निर्देशों को नरम न करने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिगड़ते जन-सुरक्षा संकट में एक आवश्यक हस्तक्षेप है। हाल के वर्षों में, देश भर में स्थानीय प्रशासन व निकाय कुत्तों के काटने की घटनाओं में लगातार हो रही चिंताजनक वृद्धि को रोकने में विफल ही रहे हैं। ऐसे में शासन व प्रशासन स्तर पर इस समस्या के निराकरण की कोई सार्थक पहल न होते देख ही, शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार, साल 2023 में तीस लाख से अधिक कुत्तों के काटने का निर्देश दर्ज किए गए थे। उसके अगले साल 2024 में रोकथाम के कोई ठोस प्रयास न होने के कारण 37 लाख मामले दर्ज किए गए। आंकड़े बता रहे हैं कि औसतन प्रतिदिन दस हजार घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं कई राज्यों व शहरों में इन घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई है। अदालत ने गौर किया कि एबीसी ढांचे की शुरुआत के बाद से लगभग दो दशक बीत जाने के बावजूद, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से लगातार बढ़ती आवाज कुत्तों की आबादी की गंभीरता को रोकने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे का विस्तार और सुदृढ़ करने के लिए निरंतर, व्यवस्थित और क्रमिक प्रयासों का स्पष्ट अभाव रहा है। अदालत ने आवाज कुत्तों से जुड़ी घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि को उजागर करने वाली कई समाचार पत्रों की रिपोर्टों का भी हवाला दिया। अदालत ने कहा कि उदयपुर में 2026 में लगभग 1,750 कुत्ते के काटने के मामले दर्ज किए गए, जबकि भीलवाड़ा में एक ही दिन में 42 लोगों को कुत्ते ने काटा। अदालत ने यह भी बताया कि तमिलनाडु में 2026 के पहले चार महीनों में लगभग 2.63 लाख कुत्ते के काटने के मामले और 17 संबंधित मौतें दर्ज की गईं। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि यह मुद्दा आवासीय इलाकों से आगे बढ़कर हवाई अड्डों और अन्य सार्वजनिक स्थानों तक फैल गया है, और यह भी बताया कि नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने 1 जनवरी, 2026 से हवाई अड्डे के टर्मिनलों में कम से कम 31 कुत्ते के काटने की घटनाओं को स्वीकार किया है। केरलम राज्य के आंकड़ों के अनुसार, वहां एक साल के भीतर ही 3.6 लाख से अधिक कुत्तों के काटने के मामले सामने आए हैं। वहीं दूसरी दिल्ली से संते नोएडा में कुछ ही महीनों में हजारों शिकायतों के बाद हॉटस्पॉट की पहचान की गई। इन शिकायतों में स्कूलों के पास उनका जमावड़ा होना, चलने में असमर्थ बुजुर्ग नागरिकों का शिकार बनना व आम नागरिकों के आवाज कुत्तों के भय में जीने के मामले उजागर हुए हैं। दरअसल, विगत में भी इस संकट के कारण समाधान के लिये शीर्ष अदालत ने सख्त निर्देश दिए थे। स्थानीय नगर निगम व नगर पालिकाओं की जवाबदेही तब की थी कि कुत्तों को शेल्टर होम ले जाकर उनकी नसबंदी की जाए और टीकाकरण किया जाए। लेकिन इस दिशा में कारगर पहल होती नर नहीं आई। वहीं तसवीर का दूसरा पहलू है कि यह संकट समाज और संस्थाओं द्वारा जानवरों के प्रति किए जाने वाले व्यवहार पर परेशान करने वाली विफलता को भी दर्शाता है। साल 2022 में मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय ने संसद में जानकारी दी थी कि देश में सबसे अधिक आवाज कुत्तों की संख्या उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में है जबकि दादरा और नगर हवेली, लक्षद्वीप और मणिपुर में सड़कों पर कोई भी आवाज कुत्ता नहीं है। हालांकि मंत्रालय ने बताया था कि 2012 के मुकामले 2019 में उत्तर प्रदेश में आवाज कुत्तों की संख्या घटकर 20.59 लाख हो गई थी। निस्संदेह, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कानूनी रूप से जानवरों को स्थानांतरित करने पर दिए गए जोर के साथ अब आश्रय स्थलों, नसबंदी केंद्रों, टीकाकरण अभियानों और पशु चिकित्सा सुविधाओं में अधिक निवेश करने की सख्त जरूरत है। निश्चय ही यह चुनौती एक जटिल

विषय है। सही मायनों में चुनौती यह भी है कि एक मानविय, जवाबदेह और प्रभावी आवाज कुत्त प्रबंधन व्यवस्था का निर्माण किया जाए, जो नागरिकों और कुत्तों, दोनों के हितों की रक्षा कर सके। सदैव से ही कुत्ते की गिनती मनुष्य के वफादार साथी के रूप में की जाती रही है। सदियों से दोनों एक साथ रहे हैं। उन कारणों की भी पड़ताल की जानी चाहिए, जिनके चलते कुत्ते अचानक आक्रामक व्यवहार दिखाने लगे हैं। निश्चय ही बढ़ता तापमान बदलते मौसमों के प्रति संवेदनशील इन जीवों को बेचैन किए हुए है। भूख व आश्रय के अभाव से उपजे असुरक्षा बोध ने भी उन्हें आक्रामक बनाने में भूमिका निभाई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि यदि राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों ने समय रहते दृढ़ता के साथ काम किया होता, तो आज स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। अदालत ने यह भी संकेत दिया कि सार्वजनिक स्थानों पर लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मुद्दे पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत के निर्देशों के बाद अब राज्यों और नगर निकायों पर संस्थागत क्षेत्रों को आवाज कुत्तों से मुक्त रखने और प्रभावी नियंत्रण नीति लागू करने का दबाव बढ़ गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लागू इन नियमों को लेकर जहां पशु प्रेमियों में निराशा है वहीं कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं और पीड़ितों को इस आदेश से जरूर खुशी मिली होगी। यह आदेश लागू है और अब सख्ती से इनको लागू में लाया जाना बाकी है। देखा है कि इन आदेशों के बाद किस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया जाता है। ये समाधान सिर्फ सरकार या स्थानीय निकायों के बूते होना संभव नहीं है। पशु प्रेमियों की बड़ी पहल के परिणाम बदलाव लाने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं।

प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक के अंक भरना आवश्यक है। इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है।

....

आड़ी और खड़ी में एवं 3-3 के वर्ण में किसी भी अंक की पुनरावृत्ति न हो इसका ध्यान जरूर रखें।

सूडोकू पहेली - 3404 का उत्तर

2	9	5	3	1	7	8	4	6
8	4	7	9	2	6	1	5	3
6	3	1	5	2	4	9	7	2
1	8	9	8	5	8	3	5	6
4	6	3	7	9	5	2	8	1
5	7	2	1	6	8	4	3	9
7	2	6	4	5	9	3	1	8
3	1	4	8	7	2	6	9	5
9	5	8	6	3	1	7	2	4

वर्ग पहेली नं. 3446

1	2	3	4	5	6
		7	8		9
10			11		
	13			14	15
16	17		18		
		19		20	21
22			23	24	
25		26	27	28	29
		30			

ऊपर से नीचे:- 1) दुश्मनी, 2) असंभव, 3) हाथ का पंजा, 4) बोलत, 5) अर्थात्, 6) निकटता, 8) दरबारी सलाम, 12) गधा, 15) बोल, 17) हिटलर, 18) हाथी, 19) हठ; प्रतिष्ठा, वैभव, 21) सावधान, 22) लंबा; खाना, 24) ठीक नहीं, 27) रक्तवाहिनी, 29) विराट. (उत्तर: अगले अंक में)

पिछली पहेली का उत्तर

मु	क्र	द	मा	आ	रं	भ	म
म	स	ल	स	ग	त		
अ	मु	क	का	य	र	ब	ब
मं	न	न	ह	ल	ल		
क	र	मा	त	नी	म	न	
के	ल	हू	त	ब	दी	ल	
श	रा	बी	चा	द	क		
ह	ख	ह	ट	क	ना	क	
नि	हा	य	त	ना	म	यु	र

बायें से दायें:- 1) अश्लील, 4) निश्चयपूर्वक, 7) मुना हुआ चाल, 9) बोली; घोषविक्रय, 10) शिखा, 11) जबरदस्त, 13) छेर; तीवर, 14) भेदभावहीनता, 16) नखटख, 18) घड़ा, 19) पुत्र, 20) अभिव्यक्ति इच्छा; तीब्रोन्माद, 22) दशकंद, 23) नय, 25) रास्ता, 26) वकीलों का समूह; मद्यकष, 28) अनुमानित, 30) कार्पनिक.

Mob. No. 08329510310

सूडोकू-पहेली-3404

4	1			7				
		4	9		1	2		
	6		2					
	7	3		6			4	
			1	7		3		
7				5				
8								3
9	2	4			1			

दुर्गापुर में प्रशासनिक बैठक : फिजूलखर्ची पर रोक, पारदर्शी शासन और जल्द चुनाव का संकेत

राज्य सरकार नगर निकायों के सुचारु संचालन को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही : शुभेंदु अधिकारी

पश्चिम बर्दवान

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गापुर में प्रशासनिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई कर्मों और शहरों में नगर निकायों का कामकाज ठप हो जाने से लोगों को असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि पंचायतों और नगरपालिकाएं बंद हैं, जिसके चलते आम लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। किसी को भी पंचायतों और नगरपालिकाओं के कामकाज को ठप करने का कोई अधिकार नहीं है।



मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रबंध विचार्य पदाधिकारी (बीडीओ) को निर्देश दिए गए हैं कि वे कल्याणकारी योजनाओं के निर्वाह कार्यान्वयन और जमीनी स्तर पर प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि बीडीओ पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी होते हैं। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी योजनाएं लागू हों। हमने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को अपनाया है और आयुष्मान भारत, विश्वकर्मा योजना और उज्वला योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाना चाहिए। शुभेंदु ने कहा कि मानसून के दौरान की तैयारियों और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना उनकी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि आज की बैठक में चर्चा किया गया चौथा मुद्दा मानसून के दौरान की तैयारियों से संबंधित है। पांचवां मुद्दा जबरन वसूली की संस्कृति को पूरी तरह से बंद करना और सरकारी राजस्व में होने वाले रिसाव को रोकना है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बर्दवान और पूर्व बर्दवान जिलों में अवैध रेत खनन के कारण राजस्व का भारी नुकसान हुआ है, और भाजपा के सत्ता में आने के बाद ऐसी खदानें बंद कर दी गईं। अधिकारी ने कहा कि वह 'डबल इंजन सरकार' के लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने आसमोल, चित्तजन, आंदोल और दुर्गापुर की उपेक्षा की। हमें दो से तीन महीने का समय और सरकारी राजस्व में होने वाले रिसाव को रोकना है। उन्होंने यह भी दावा किया कि पश्चिम बर्दवान और पूर्व बर्दवान जिलों में अवैध रेत

आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामले में हाई कोर्ट ने नई तीन सदस्यी एसआईटी की गठित

सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने की होगी जांच कोलकाता, समाज्ञा

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी कर दुष्कर्म-हत्या मामले में गुरुवार को सीबीआई की तीन सदस्यी विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया, जो पीड़िता प्रशिक्षु डॉक्टर द्वारा भी अगस्त 2024 की रात को भोजन करने से लेकर उनके अंतिम संस्कार तक के घटनाक्रम की जांच करेगी। आरोप हैं कि सबूतों को नष्ट किया गया और घटना के तुरंत बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई। न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थकर घोष की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई के संयुक्त निदेशक (पूर्वी क्षेत्र) एसआईटी का नेतृत्व करेंगे। टीम के अन्य दो सदस्यों का चयन न्यायालय के आदेश के 48 घंटों के भीतर किया जाएगा। पीठ ने कहा कि इस भयावह घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए, तीन सदस्यी एसआईटी साक्ष्यों को नष्ट करने और मामले को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। एसआईटी को घटना की रात प्रशिक्षु डॉक्टर के अस्पताल में भोजन करने से लेकर अगली शाम उनके अंतिम संस्कार तक की घटनाओं की जांच करने का निर्देश दिया गया है। अदालत ने एसआईटी को 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिस दिन मामले की अगली सुनवाई होगी। उल्लेखनीय है कि पीड़िता के माता-पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म और हत्या की विस्तृत जांच का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस गंभीर अपराध में एक से अधिक व्यक्ति शामिल थे।



सरकारी अधिकारियों के लिए सख्त गाइडलाइन, बिना अनुमति मीडिया में बयान देने पर रोक

कोलकाता, समाज्ञा

राज्य सरकार ने एक परिपत्र जारी कर अपने कर्मचारियों के लिए लागू आचरण नियमों को दोहराया है, जिनके तहत बिना अनुमति मीडिया के साथ आधिकारिक दस्तावेज या जानकारी साझा करने और सार्वजनिक रूप से राज्य या केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर रोक है।

मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि अखिल भारतीय सेवाओं, पश्चिम बंगाल सिविल सेवा, पश्चिम बंगाल पुलिस सेवा तथा अन्य राज्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू मौजूदा आचरण नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। एक अधिकारी ने कहा कि इसका उद्देश्य कर्मचारियों को मीडिया से बातचीत और सूचना-ओं के प्रसार से संबंधित आचरण नियमों में पहले से मौजूद प्रावधानों की याद दिलाना है। परिपत्र में एआईएस आचरण नियम, 1968 और पश्चिम बंगाल सरकारी कर्मचारी आचरण नियम, 1959 के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। अधिकारी ने बताया कि सरकारी कर्मचारियों को बिना अनुमति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मीडिया के साथ कोई भी दस्तावेज या जानकारी साझा करने से प्रतिबंधित किया गया है। इसमें कर्मचारियों को पूर्व अनुमति के बिना निजी तौर पर निर्मित या प्रायोजित मीडिया कार्यक्रमों में भाग लेने और सरकार से मंजूरी के बिना लेख, प्रसारण या प्रकाशन में योगदान देने से भी प्रतिबंधित किया गया है। परिपत्र में यह भी कहा गया है कि कर्मचारियों को किसी भी मीडिया में प्रकाशन, संवाद, कथन, प्रसारण या योगदान के माध्यम से राज्य या केंद्र सरकार की नीतियों या निर्णयों की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने की अनुमति नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक संचार जिससे राज्य और केंद्र सरकारों के बीच, राज्यों के बीच या विदेशों के साथ संबंधों में तनाव पैदा हो सकता है, वह भी प्रतिबंधित है। अधिकारी ने बताया कि परिपत्र में केवल 'मौजूदा सेवा आचरण मानदंडों' का उल्लेख किया गया है। यह निर्देश राज्य सरकार द्वारा पारित रूप से वित्त पोषित स्वायत्त निकायों, बोर्ड, निगमों, उपक्रमों और शैक्षणिक संस्थानों के कर्मचारियों पर भी लागू होता है।

राज्य में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 500 कंपनियों की तैनाती 20 जून तक बढ़ायी गयी

कोलकाता, समाज्ञा : केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के अनुरोध पर केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की 500 कंपनियों की तैनाती चुनाव बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 20 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। गृह मंत्रालय ने एक आधिकारिक विज्ञापन में कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्रीय बलों की तैनाती चुनाव के बाद अक्टूबर के अंत तक बढ़ाने का अनुरोध किया था। मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार के अनुरोध पर विचार किया गया है। राज्य के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि सीएपीएफ की 500 कंपनियां 20 जून तक राज्य में तैनात रहेंगी। इनमें सीआरपीएफ की 200, बीएसएफ की 150 और सीआईएसएफ, आईटीवीपी और एसएसबी की 50-50 कंपनियां शामिल हैं। राज्य सरकार के एक विज्ञापन में बताया कि विधानसभा चुनाव के बाद संवेदनशील क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद के लिए इन बलों को रखा गया है। अधिकारी ने कहा कि तैनाती का उद्देश्य संवेदनशील क्षेत्रों में शांति सुनिश्चित करना और किसी भी अशान्ति घटना को रोकना है। राज्य पुलिस और सीएपीएफ के बीच समन्वय जारी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में तैनात केंद्रीय बलों के लिए आवश्यक साजोसामान, आवास और अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा है।

कोलकाता, समाज्ञा : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी को पिछले महीने एक जनसभा में दिए गए उनके बयानों को लेकर दर्ज प्राथमिकी में 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया। न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी सांसद के लिए इस तरह के अनुचित बयान देना सही है। न्यायमूर्ति सीगत भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी द्वारा पेश होने के लिए भेजे गए नोटिस का अनुपालन करने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें

अभिषेक बनर्जी को राहत, हाई कोर्ट ने 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक

कोलकाता, समाज्ञा : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी को पिछले महीने एक जनसभा में दिए गए उनके बयानों को लेकर दर्ज प्राथमिकी में 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया। न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी सांसद के लिए इस तरह के अनुचित बयान देना सही है। न्यायमूर्ति सीगत भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी द्वारा पेश होने के लिए भेजे गए नोटिस का अनुपालन करने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें

कोलकाता, समाज्ञा : कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अभिषेक बनर्जी को पिछले महीने एक जनसभा में दिए गए उनके बयानों को लेकर दर्ज प्राथमिकी में 31 जुलाई तक दंडात्मक कार्रवाई से संरक्षण प्रदान किया। न्यायालय ने यह भी सवाल उठाया कि क्या किसी सांसद के लिए इस तरह के अनुचित बयान देना सही है। न्यायमूर्ति सीगत भट्टाचार्य ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव बनर्जी को जांच में सहयोग करने और जांच अधिकारी द्वारा पेश होने के लिए भेजे गए नोटिस का अनुपालन करने का निर्देश दिया। अदालत ने उन्हें

NAME CHANGE

I, ARUN DAS Unit-58 WEU Ro. VIII - P.O. Tilkhola, P.S-Moyna, Dist-Purba Medinipur, State-West Bengal, Pin-721629. My service No-15679641P. Rank. HAV. I am citizen of India. SAHADEB DAS is my father. In my Army Service Records, My Father's Name & D.O.B is wrongly recorded as SANDYA RANI DAS - 01.07.1967. As per her identified Document/Aadhaar card, her correct Name & D.O.B is SAHADEB DAS 01.01.1963 which may be amended accordingly for all further purposes. I am producing this Affidavit for the purpose of evidence mother's Name & D.O.B. Affidavit date -12.05.2026, Notary Public at Tamuk. SAHADEB DAS and SAHADEB DAS both are the same and one identical person.

Khanakul-II Development Block
Senhat, Rajhati, Bandar, Hooghly

NOTICE INVITING TENDER

The BDO Kh-II, Nlet No. 01/BDO KH-II/2026-27, dt. 19.05.2026. Tender ID- 2026_ZPHD_1024804_1 for C.C. Road. Bids Submission Ends 06.06.2026 up to 03.00 P.M. For details visit wbenders.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Khanakul-II Development Block

GARBHETA-1 DEVELOPMENT BLOCK
GARBHETA-1, PASCHIM MEDINIPUR
ABRIDGED TENDER NOTICE

e-NIT No.-WBPMID/GST/1/BDO/Tribal Dev./State Development Fund (25-26)/eNIT-01(02)/2026-27

2 (two) nose e-Tender are invited by the Block Development Officer, Garbheta-1 Dev. Block from the reliable bonafide resourceful bidders of the following works under Tribal Development (State Fund) within Amtaloga & Dhudika Gram Panchayat having e-Tender ID: 2026_DMPMM 5014182_1 and 2026_DMPMM 5014182_2. Details may be had from the website: https://tenders.wb.gov.in/nicgesp_app. Publishing Date: 18.05.2026 at 6:00 P.M. Bid submission start on 19.05.2026 at 10:00 A.M. Bid submission end 01.06.2026 at 04:00 P.M

Sd/-
Block Development Officer
Garbheta-1 Development Block.

पूर्व रेलवे

ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

ई-नीलामी सूचना सं. : सीओएम/पीसी/एचडब्ल्यूए/26/14 दिनांक : 19.05.2026

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व रेलवे, हावड़ा मंडल, नई डीआरएम बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रेल म्यूजियम के पास, हावड़ा-711101 द्वारा हावड़ा मंडल के तहत हावड़ा रेलवे स्टेशन (ओल्ड कॉम्प्लेक्स एवं न्यू कॉम्प्लेक्स) में रिटेल स्टोर की स्थापना, परिचालन एवं रखरखाव का अनुबंध प्रदान करने के लिए ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है।

हावड़ा मंडल के तहत विभिन्न स्टेशनों पर एटीवीएम फेसिलिटेटर की नियुक्ति

एटीवीएम के माध्यम से अनारक्षित टिकट जारी करने हेतु

आवेदन सूचना सं. : सीओएम/सीएफ/एटीवीएम-एफएस/एचडब्ल्यूए/26/2 दिनांक 21.05.2026

हावड़ा मंडल में स्टेशनों पर स्थापित ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीनों (एटीवीएम) के माध्यम से अनारक्षित टिकट जारी करने हेतु फेसिलिटेटरों की नियुक्ति के लिए सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों और आम जनता से वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, हावड़ा मंडल आवेदन आमंत्रित करते हैं।

पूर्व रेलवे

ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

ई-नीलामी सूचना सं. : सीओएम/पीसी/एचडब्ल्यूए/26/14 दिनांक : 19.05.2026

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व रेलवे, हावड़ा मंडल, नई डीआरएम बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रेल म्यूजियम के पास, हावड़ा-711101 द्वारा हावड़ा मंडल के तहत हावड़ा रेलवे स्टेशन (ओल्ड कॉम्प्लेक्स एवं न्यू कॉम्प्लेक्स) में रिटेल स्टोर की स्थापना, परिचालन एवं रखरखाव का अनुबंध प्रदान करने के लिए ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है।

परीक्षार्थीगण ध्यान दें!!

सियालदह मंडल की ट्रेनों के आवागमन में विशेष व्यवस्था

वेस्ट बंगाल जॉइंट एंजिन एग्जामिनेशन (इन्फ्यूबीजेई-2026) और सिविल सर्विस (प्रिलिमिनी) एग्जाम 2026 के लिए अतिरिक्त भीड़ से निपटने के लिए, सियालदह मंडल में रिवार को रद्द रहने वाली उभरगरीब ट्रेन सेवाएं दिनांक 24.05.2026 (रिवार) को दिन की पहली निर्धारित सेवा से शुरू करके सुबह 11.00 बजे तक (यात्रा शुरू के स्टेशन से प्रस्थान के आधार पर) अपने समाह के दिनों की अनुसूची के अनुसार चलेंगी।

सभी वातानुकूलित इएमयू लोकल ट्रेनें रिवार की अनुसूची का अनुसरण करेंगी। अर्थात्, निम्नलिखित वातानुकूलित लोकल ट्रेनें दिनांक 24.05.2026 (यात्रा शुरू की तारीख) को चलेंगी: (1) 31638/31637 रानाघाट-सियालदह-रानाघाट वातानुकूलित इएमयू लोकल (2) 31847/31848 सियालदह-कृष्णनगर सिटी-सियालदह वातानुकूलित इएमयू लोकल।

मंडल रेल प्रबंधक, सियालदह

पूर्व रेलवे

पूर्व रेलवे

ई-नीलामी आमंत्रण सूचना

ई-नीलामी सूचना सं. : सीओएम/पीसी/एचडब्ल्यूए/26/13 दिनांक : 19.05.2026

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, पूर्व रेलवे, हावड़ा मंडल, नई डीआरएम बिल्डिंग, चतुर्थ तल, रेल म्यूजियम के पास, हावड़ा-711101 द्वारा हावड़ा मंडल के तहत हावड़ा रेलवे स्टेशन (ओल्ड कॉम्प्लेक्स एवं न्यू कॉम्प्लेक्स) में रिटेल स्टोर की स्थापना, परिचालन एवं रखरखाव का अनुबंध प्रदान करने के लिए ई-नीलामी आमंत्रित की जाती है।

सियालदह-लालगोला खंड में स्पेशल इएमयू सेवाएं

ई-उल-अधा के कारण सियालदह-लालगोला खंड में यात्रियों की प्रत्याशित भारी भीड़ को संभालने के लिए, निम्नलिखित इएमयू स्पेशल ट्रेनें निम्नानुसार चलाई जाएंगी:

25.05.2026 को				
03119 सियालदह-लालगोला उप इएमयू स्पेशल				
स्टेशन	आ.	आ.	प्र.	प्र.
सियालदह	-	-	15.20	15.20
दमदम जंक्शन	-	15.32	15.33	15.33
बैरकपुर	15.55	15.56	15.56	15.56
नैहाटी	16.21	16.22	16.22	16.22
रानाघाट	17.03	17.04	17.04	17.04
कृष्णनगर सिटी जंक्शन	17.42	17.52	17.52	17.52
बहरमपुर कोर्ट	19.27	19.28	19.28	19.28
लालगोला	20.20	-	-	-

26.05.2026 को				
03120/03119 लालगोला-सियालदह-लालगोला इएमयू स्पेशल				
लागोला-सियालदह डाउन इएमयू	03120	03119	सियालदह-लालगोला अप इएमयू	03119
आ.	प्र.	स्टेशन	आ.	प्र.
09.55	-	सियालदह	-	15.20
09.34	09.35	दमदम जंक्शन	15.32	15.33
09.09	09.10	बैरकपुर	15.55	15.56
08.48	08.49	नैहाटी	16.21	16.22
08.07	08.08	रानाघाट	17.03	17.04
07.21	07.31	कृष्णनगर सिटी जंक्शन	17.42	17.52
05.35	05.36	बहरमपुर कोर्ट	19.27	19.28
-	04.50	लालगोला	20.20	-

27.05.2026 को				
03120/03121 लालगोला-सियालदह-लालगोला इएमयू स्पेशल				
लागोला-सियालदह डाउन इएमयू	03120	03121	सियालदह-लालगोला अप इएमयू	03121
आ.	प्र.	स्टेशन	आ.	प्र.
09.55	-	सियालदह	-	11.55
09.34	09.35	दमदम जंक्शन	12.07	12.08
09.09	09.10	बैरकपुर	12.29	12.30
08.48	08.49	नैहाटी	12.57	12.58
08.07	08.08	रानाघाट	13.44	13.45
07.21	07.31	कृष्णनगर सिटी जंक्शन	14.16	14.25
05.35	05.36	बहरमपुर कोर्ट	15.57	15.58
-	04.50	लालगोला	16.55	-

03154 लालगोला-रानाघाट डाउन इएमयू स्पेशल				
लागोला-सियालदह डाउन इएमयू	03120	03122	लालगोला-सियालदह डाउन इएमयू	03122
आ.	प्र.	स्टेशन	आ.	प्र.
-	-	सियालदह	19.10	-
-	-	दमदम जंक्शन	18.30	18.31
-	-	बैरकपुर	18.52	18.53
-	-	नैहाटी	18.06	18.07
-	09.50	रानाघाट	17.22	17.23
10.21	10.22	कृष्णनगर सिटी जंक्शन	16.40	16.50
11.54	11.55	बहरमपुर कोर्ट	15.04	15.05
12.50	-	लालगोला	-	14.15

पूर्व रेलवे

टिप्पणी: उपर्युक्त सभी इएमयू स्पेशल ट्रेनें मार्ग में सभी स्टेशनों पर चक्की।

मंडल रेल प्रबंधक, सियालदह

हमें यहाँ देखें: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

सरकारी खरीद में अब अनिवार्य होंगी सीवीसी की गाइडलाइन

भ्रष्टाचार रोकने को शुभेदु सरकार का बड़ा कदम

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य की पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में विभिन्न सरकारी परियोजनाओं में भ्रष्टाचार, 'कट-मनी' और कमीशनखोरी के लगे अनगिनत आरोपों से सबक लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी के नेतृत्व वाली नई राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। राज्य में सरकारी खरीद प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों में अब केंद्रीय सतर्कता



आयोग (सीवीसी) के दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। चालू समाह में राज्य के वित्त विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना में इस बड़े फैसले की घोषणा की गई है। वित्त विभाग की ओर से जारी इस अधिसूचना के

अनुसार, अब से राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागों, निगमों और सरकारी संस्थानों को किसी भी वस्तु की खरीद, सेवाओं को लेने तथा विभिन्न कार्यों के टेंडर जारी करते समय सीवीसी के निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। गौरतलब है कि अब तक राज्य में सरकारी खरीद के लिए मुख्य रूप से बंगाल के अपने 'फाइनेंशियल रूलर्स' का पालन किया जाता था। प्रशासनिक हलकों के एक वर्ग का दावा है कि पूर्व में इस प्रक्रिया की आड़ में कई बार बड़े

पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप उठ चुके हैं। नवान्न (राज्य सचिवालय) के सूत्रों के मुताबिक, पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार के दौर में विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन और टेंडर प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर हुई अनियमितताओं के महेनजर ही नई भाजपा सरकार ने यह सख्त रुख अपनाया है। प्रशासन का मानना है कि सीवीसी के दिशानिर्देश लागू होने से सरकारी खरीद में न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि पक्षपात और कमीशनखोरी जैसी आदतों पर

भी पूरी तरह से लगाम लगेगी। राज्य के वित्त सचिव प्रभात मिश्रा द्वारा हस्ताक्षरित इस अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मौजूदा वित्तीय नियमों के साथ-साथ सीवीसी के सभी दिशानिर्देशों का पालन करना अब बाध्यकारी होगा। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी शुरुआत से ही भ्रष्टाचार के सभी अधिकारियों के मुताबिक, 19 मई को वाराणसी इकाई की टीम बलिया पहुंची और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आरोपी के कब्जे से हथियारों और कारतूसों का खजौरा बरामद किया गया। एसीएफ निरीक्षक अनिल कुमार सिंह की

सीएम शुभेदु के पीए की हत्या मामले में पांचवी गिरफ्तारी, बलिया से आरोपी गिरफ्तार

बलिया/कोलकाता : मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस के विशेष कार्य बल (एसटीएफ) ने बलिया जिले से एक कथित अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपी का नाम फेफना थाना क्षेत्र के थरहनपुरा गांव निवासी नवीन कुमार सिंह (35) है। उसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा साझा की गई जानकारी के आधार पर पकड़ा गया। एसीएफ अधिकारियों ने मुताबिक, 19 मई को वाराणसी इकाई की टीम बलिया पहुंची और तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आरोपी के कब्जे से हथियारों और कारतूसों का खजौरा बरामद किया गया। एसीएफ निरीक्षक अनिल कुमार सिंह की

शिकायत पर फेफना थाने में शख् अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। पृष्ठताछ में आरोपी ने कथित तौर पर बताया कि बलिया के ही एक अन्य अपराधी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मन्नू और उसके दो सहयोगियों ने उसे हथियारों से भरा बैग सौंपा था। बाद में, एसीएफ ने राष्ट्रीय राजमार्ग किनारे स्थित एक कार शोरूम से हथियार बरामद किए, जिनमें तीन पिस्तौल, दो रिवाल्वर और 45 कारतूस शामिल हैं। पुलिस के अनुसार, बरामद हथियारों में एक पिस्तौल अमेरिका निर्मित भी है। अधिकारियों ने बताया कि नवीन कुमार सिंह के खिलाफ पहले से भी रंगदारी और मारपीट के मामले दर्ज आई थी और वह इनके घरेलू में न्यायिक हिरासत में मऊ जेल भेज दिया गया है।

से खरीदी गई थी : पुलिस मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या में इस्तेमाल की गई कार उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से खरीदी गई थी। पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी। बांसडीह रोड थाना क्षेत्र के फुलवरिया गांव निवासी जितेंद्र सिंह ने दावा किया कि 'मिर्चू' उर्फ दीपक नामक व्यक्ति ने पिछले वर्ष अक्टूबर में उसके माध्यम से 35 हजार रुपये में एक निसाना माइक्रा कार खरीदी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यही वाहन बाद में एक मई को ज्ञानेंद्र प्रताप उर्फ मन्नू को 50 हजार रुपये में बेच दिया गया। जितेंद्र ने संवाददाताओं को बताया कि हाल ही में सीबीआई की एक टीम उनके घर आई थी और वाहन के संबंध में पृष्ठताछ की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जांच एजेंसी को पूरी जानकारी उपलब्ध कराई है।

गोदरेज एटंप्राइजेशन ग्रुप ने 19% की वृद्धि के साथ जैव विविधता के संरक्षण को मजबूत किया

कोलकाता : अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर, गोदरेज एटंप्राइजेशन ग्रुप ने अपने 'गुड एंड ग्रीन' दृष्टिकोण और विज्ञान आधारित स्थिरता दृष्टिकोण से प्रेरित होकर, अपने सभी व्यवसायों और समुदायों में जैव विविधता संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। जैव विविधता संरक्षण कंपनी के व्यापक स्थिरता एजेंडे में शामिल है, जो संसाधन दक्षता, जलवायु कार्बन और ज़िम्मेदार सोर्सिंग पर केंद्रित है। तेजश्री जोशी, हेड ऑफ एनवायरनमेंटल सस्टेनेबिलिटी, गोदरेज एटंप्राइजेशन ग्रुप ने कहा, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हमारे लिए एक बिल्कुल सही अवसर है, जब हम मापने योग्य, विज्ञान-आधारित और पर्याप्त-समृद्ध पहलों के माध्यम से व्यावसायिक प्रथाओं में जैव विविधता संरक्षण को शामिल करने की अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर सकें।

भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट के आरोप में परमब्रत और स्वास्तिका के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य में 2021 के चुनाव के बाद हुई हिंसा के दौरान सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में अभिनेता परमब्रत चट्टोपाध्याय और अभिनेत्री स्वास्तिका मुखर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह शिकायत गरियाहाट थाने में अधिवक्ता जॉयदीप सेन द्वारा दर्ज कराई गई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दोनों कलाकारों ने सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियों की थीं जो मई 2021 में विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद तनावपूर्ण माहौल में राजनीतिक हिंसा को भड़का सकती थीं। शिकायत के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस द्वारा बहुमत का आंकड़ा पार करने के बाद परमब्रत ने दो मई 2021 को 'एक्स' (तब ट्विटर) पर पोस्ट किया था कि आज के दिन को विश्व पिटाई दिवस घोषित



किया जाए। स्वास्तिका ने कथित तौर पर उस पोस्ट का जवाब देते हुए लिखा था कि हाहाहा, जाने दो। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इस तरह की टिप्पणियों से राज्य भर में चुनाव के बाद की आशांति के दौरान राजनीतिक शत्रुता और हिंसा का माहौल बना। कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गरियाहाट थाने में शिकायत प्राप्त हुई है और प्राथमिकी के उपयोग को कम करने के निर्देश के अनुरूप की गई है। कौंथम ने कहा कि उन निर्देशों

मुख्यमंत्री की बैठक में शामिल होने बस से पहुंचे पुरुलिया के अधिकारी

कोलकाता, समाज्ञा : राज्य सरकार के व्यव पर अंकुश लगाने के निर्देश के अनुरूप, पुरुलिया जिले के वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री शुभेदु अधिकारी द्वारा बुलाई गई समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए बस से दुर्गापुर पहुंचे। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दुर्गापुर सिटी सेंटर के सूजनी सभागार में बैठक में राज्य के पांच पश्चिमी जिलों पुरुलिया, बांकुड़ा, पश्चिम बर्दवान, पूर्व बर्दवान और बीरभूम के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भाग ले रहे हैं। पुरुलिया के जिलाधिकारी सुधीर कौंथम ने कहा कि बस यात्रा की यह पहल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील और राज्य सरकार के सरकारी वाहनों के उपयोग को कम करने के निर्देश के अनुरूप की गई है। कौंथम ने कहा कि उन निर्देशों



का पालन करते हुए, हम दुर्गापुर में मुख्यमंत्री की विकास समीक्षा बैठक में भाग लेने के लिए बस से यात्रा कर रहे हैं। सुबह करीब 9.45 बजे, जिलाधिकारी, अतिरिक्त

जिलाधिकारी, उप-विभागीय अधिकारियों और बीडीओ को ले जाने वाली दो बसें जिला प्रशासनिक मुख्यालय से दुर्गापुर के लिए रवाना हुईं।

शिवपुर में बमबाजी मामले के फरार तीन आरोपी मुंबई से गिरफ्तार, मास्टरमाइंड भी पकड़ा गया

मुंबई/कोलकाता : मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-6 ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हावड़ा जिले के शिवपुर थाना क्षेत्र में बमबाजी और फायरिंग मामले में फरार चल रहे तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुंबई के देवनार इलाके से गिरफ्तार आरोपियों में मामले का मुख्य साजिशकर्ता भी शामिल है। मुंबई क्राइम ब्रांच के अनुसार, तीनों आरोपी पश्चिम बंगाल में वारदात को अंजाम देने के बाद अपनी पहचान छिपाकर देवनार स्थित एकटा एसआरए बिल्डिंग के एक कमरे में रह रहे थे। मुंबई पुलिस को हावड़ा पुलिस से इनपुट मिला कि शिवपुर बमबाजी मामले के आरोपी मुंबई में छिपे हुए हैं। गुप्त सूचना मिलने के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट-6 ने जाल बिछाकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों का नाम शमीम अहमद अब्दुल रशीद (40), जमील अख्तर अली (43) और अन्वताब अनवर खुशीद अनवर (44) हैं। क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के मुताबिक, पृष्ठताछ में आरोपियों ने शिवपुर बमबाजी और फायरिंग मामले में अपनी संलिप्तता

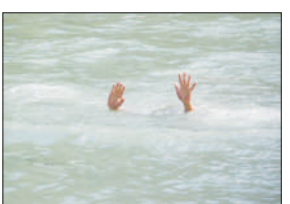


स्वीकार कर ली है। जांच में यह भी सामने आया है कि तीनों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है। पुलिस ने बताया कि शिवपुर थाने की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और आरोपियों को हिरासत में लेने की प्रक्रिया जारी है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद तीनों को ट्रांजिट रिमांड पर पश्चिम बंगाल पुलिस को सौंप दिया जाएगा। मुंबई क्राइम ब्रांच ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दर्ज मामले में आगे की जांच शिवपुर पुलिस द्वारा की जाएगी।

महानंदा नदी में नहाने उतरे दो बच्चे लापता, तलाश जारी

मालदह : पुरातन मालदह जिले में गुरुवार को महानंदा नदी में नहाने के दौरान दो नाबालिग बच्चे डूब गए। घटना पुरातन मालदह नगरपालिका के वार्ड दो स्थित बांशहाट घाट की है। लापता बच्चों की पहचान अर्पण सरकार (10) और बासुदेव हालदार (8) के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, अर्पण दक्षिण दिनाजपुर जिले के कुशमंडी का रहने वाला था और अपने मामा के घर बांशहाट आया हुआ था, जबकि देव हालदार स्थानीय निवासी था। बताया जा रहा है कि गुरुवार की दोपहर दोनों बच्चे अपने कुछ दोस्तों के साथ महानंदा नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान अचानक गहरे पानी और तेज धारा में बहकर दोनों डूब गए। घटना के

बाद साथ मौजूद बच्चों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना पाकर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। आपदा प्रबंधन टीम को भी बुलाया गया, लेकिन काफी देर तक तलाशी के बावजूद दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है। फिलहाल, प्रशासन की ओर से नदी में तलाशी अभियान जारी है।



बाद साथ मौजूद बच्चों के शोर मचाने पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। सूचना पाकर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची। आपदा प्रबंधन टीम को भी बुलाया गया, लेकिन काफी देर तक तलाशी के बावजूद दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। इस घटना से इलाके में शोक का माहौल है। फिलहाल, प्रशासन की ओर से नदी में तलाशी अभियान जारी है।

पूर्व रेलवे का स्वच्छता अभियान तेज, सियालदह मंडल में एजीएम ने किया व्यापक निरीक्षण

कोलकाता, समाज्ञा : पूर्व रेलवे द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छता जागरूकता अभियान के दूसरे चरण के तहत सियालदह मंडल में गुरुवार को व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया गया। पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देउस्कर के नेतृत्व में 16 मई से 30 मई 2026 तक विशेष स्वच्छता अभियान संचालित किया जा रहा है। इसी के तहत रेलवे प्रशासन ने 30 मिन्ट क्लिनिनेस चैलेंज की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखना है। अभियान की जमीनी स्थिति का जायजा लेने

के लिए पूर्व रेलवे के अतिरिक्त महाप्रबंधक शीलेंद्र प्रताप सिंह ने सियालदह मंडल का उच्चस्तरीय निरीक्षण किया। उनके साथ उप महाप्रबंधक (जनरल), अतिरिक्त मंडल रेल प्रबंधक (ऑपरेशन) तथा वरिष्ठ मंडल यांत्रिक अभियंता (पर्यावरण एवं हाउसकीपिंग प्रबंधन) भी मौजूद रहे। निरीक्षण की शुरुआत सियालदह रेलवे स्टेशन से हुई। इसके बाद टीएम ने विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण के जरिए सियालदह से पार्क सर्कस रेलवे स्टेशन तक रेलवे ट्रेनों की साफ-सफाई का जायजा लिया। इस दौरान बालीगंज रेलवे स्टेशन, ब्रेस ब्रिज रेलवे स्टेशन,

संतोषपुर रेलवे स्टेशन और नंगी रेलवे स्टेशनों पर स्काउट्स एवं गाइड्स की ओर से स्वच्छता रैलियां निकाली गईं। निरीक्षण का समापन बजबज रेलवे स्टेशन में हुआ, जहां स्टेशन परिसर, पार्किंग, पे-एंड-यूज शौचालय, खाद्य स्टॉल और वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉलों की जांच की गई। डिब्बागंजन अंतकूल शौचालयों और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग केबिन का भी निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने कहा कि अभियान का उद्देश्य केवल सफाई नहीं, बल्कि यात्रियों में स्वच्छ यात्रा की स्थायी आदत विकसित करना है।

इस्यु मोटर्स इंडिया ने पेश किया डी-मैक्स एस-कैब का नया लीजिंग मॉडल

कोलकाता, समाज्ञा : इस्यु मोटर्स इंडिया ने अपने लोकप्रिय कर्माशियल वाहन इस्यु डी-मैक्स एस-कैब के लिए नया लीजिंग सॉल्यूशन लॉन्च किया है। कंपनी का दावा है कि इस पहल से व्यवसाय मालिकों और फ्लीट ऑपरेटर्स को बिना बड़े निवेश के आधुनिक और भरोसेमंद वाहन उपलब्ध हो सकेंगे। नई योजना के तहत ग्राहक केवल 38,999 रुपये प्रति माह की शुरुआती लागत पर वाहन लीज पर ले सकेंगे। इसमें डाउन पेमेंट, रिसेप्ट्स, इश्योरेंस और सर्विसिंग जैसे अतिरिक्त खर्च शामिल नहीं होगा। कंपनी के अनुसार, पारंपरिक फाइनेंसिंग मॉडल की तुलना में ग्राहकों को 1.81 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है। इस्यु मोटर्स इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेश मित्तल ने कहा कि यह पहल उद्यमियों के लिए कर्माशियल वाहन संचालन को अधिक किफायती और सुविधाजनक बनाएगी। कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को बेहतर वित्तीय लचीलापन और संचालन क्षमता उपलब्ध कराना है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के 52 कर्मचारियों को अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति



संकोटोरिया/कोलकाता : ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा 52 कर्मचारियों को सम्मानित करने हेतु एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिन्होंने विभागीय परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति प्राप्त की। इस कार्यक्रम में सतीश झा, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, मॉ. अंजर आलम, निदेशक (वित्त), गुंजन कुमार सिन्हा, निदेशक (मानव संसाधन) तथा गिरीश गोपीनाथन नायर, निदेशक (तकनीकी) सहित विभिन्न विभागाध्यक्षों एवं अन्य कर्मचारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। प्रबंधन ने नव-पदोन्नत कर्मचारियों को उनकी कड़ी मेहनत,

सम्पन्न एवं उपलब्धि के लिए बधाई दी। पदोन्नत कर्मचारियों ने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की तथा कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विकास एवं करियर उन्नति के अवसरों के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम के दौरान सभी पदोन्नत कर्मचारियों को अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं निदेशकों द्वारा सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल समन्वय एवं संचालन दिव्यज्योती घोष, विभागाध्यक्ष (नियोजन एवं भर्ती) द्वारा किया गया तथा धन्यवाद ज्ञापन अखीर मुखोपाध्याय, विभागाध्यक्ष (प्रशासन) द्वारा प्रस्तुत किया गया।



फलता में पुनर्मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ एवं भारी संख्या में निर्भय होकर मतदाताओं ने मताधिकार किया

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने हिंदुस्तान जिंक के दरीबा कॉम्प्लेक्स का किया दौरा

कोलकाता, समाज्ञा : केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राजस्थान स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के राजपुरा-दरीबा कॉम्प्लेक्स का दौरा कर कंपनी का आधुनिक तकनीकी, सुरक्षा व्यवस्था और सामुदायिक विकास पहलों की सराहना की। दौरे के दौरान उन्होंने विश्व की प्रमुख चांदी उत्पादक खदानों में शामिल सिंटेसर खुर्द माइन और दरीबा स्मॉलिंग कॉम्प्लेक्स की संचालन प्रणाली का अवलोकन किया। मंत्री ने कंट्रोल रूम, सेल हाउस और कैथोड वार्ड का निरीक्षण करने के साथ टेली-रिमोट ऑपरेशन के लिए फिलिंग-जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की जानकारी ली। उन्होंने देश की पहली महिला मानव रस्क्यू टीम के लाइव प्रदर्शन की भी सराहना की। श्री रेड्डी ने कहा कि

कंपनी की कार्यप्रणाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत 2047' के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार माइनिंग, घरेलू क्षमता बढ़ाने और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से भारत खनिज क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दौरे के दौरान मंत्री ने श्रमिकों के साथ भोजन किया और महिला माइनिंग इंजीनियरों से संवाद किया। उन्होंने कंपनी की शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और स्वच्छ पेयजल से जुड़ी सीएसएआर पहलों की भी समीक्षा की। मंत्री ने कहा कि हिंदुस्तान जिंक न केवल माइनिंग क्षेत्र में बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है।

केएमसी ने आरजी कर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के अवैध निर्माण को तोड़ने का दिया आदेश



लेन स्थित इस मकान के खिलाफ अंशुमान सरकार नामक व्यक्ति ने अवैध निर्माण की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले पर चली लंबी सुनवाई के बाद, गत 14 मई को निगम ने अंतिम आदेश पारित किया। आदेश के तहत मकान की



छत पर बने अवैध हिस्से को अगले 45 दिनों के भीतर पूरी तरह से ध्वस्त करना होगा। निगम की जांच और आधिकारिक मानचित्र के मुताबिक, इस इमारत में मुख्य रूप से तीन नियमों का धोरा उल्लंघन पाया गया है। छत पर बिना किसी अनुमति के 5.425 वर्ग मीटर क्षेत्र में 2.05 मीटर ऊंची एक 'परगोला' (छजा जैसी संरचना) खड़ी कर दी गई थी, जो मूल बिल्डिंग प्लान का हिस्सा नहीं थी। इसके अलावा, लिफ्ट के मशीन रूम तक पहुंचने के लिए छत पर एक लोहे की युमावदार सीढ़ी लगाई गई थी और दूसरी मंजिल पर एक दरवाजे की

जगह ईट की दीवार खड़ी कर दी गई थी। निगम की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्माण कार्य केएमसी के 2009 के बिल्डिंग एक्ट की धारा 133 और 134 का सीधा उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने इस अवैध ढांचे को तुरंत हटाने की पुरजोर मांग की, वहीं दूसरी तरफ संदीप घोष की ओर से भी यह स्वीकार किया कि यह परगोला 'कम्ल्सीयन प्लान' में शामिल नहीं था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोलकाता नगर निगम के विशेष अधिकारी ने इस अवैध निर्माण को 45 दिनों के भीतर जमींदोर करने का अंतिम फरमान सुना दिया है।

जगह ईट की दीवार खड़ी कर दी गई थी। निगम की रिपोर्ट के अनुसार, यह निर्माण कार्य केएमसी के 2009 के बिल्डिंग एक्ट की धारा 133 और 134 का सीधा उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता ने इस अवैध ढांचे को तुरंत हटाने की पुरजोर मांग की, वहीं दूसरी तरफ संदीप घोष की ओर से भी यह स्वीकार किया कि यह परगोला 'कम्ल्सीयन प्लान' में शामिल नहीं था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोलकाता नगर निगम के विशेष अधिकारी ने इस अवैध निर्माण को 45 दिनों के भीतर जमींदोर करने का अंतिम फरमान सुना दिया है।

डब्ल्यूबीजेई और सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए 24 मई को चलेगी अतिरिक्त लोकल ट्रेनें

कोलकाता, समाज्ञा : पश्चिम बंगाल जॉइंट एंट्रेंस एजामिनेशन (डब्ल्यूबीजेई)-2026 और सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा-2026 के दौरान परीक्षार्थियों और यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए सियालदह मंडल ने 24 मई को अतिरिक्त उपनगरीय ट्रेन सेवाएं चलाने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार, रविवार को बंद रहने वाली कई उपनगरीय लोकल सेवाएं 24 मई को कार्यदिवस की समय-सारणी के अनुसार संचालित की जाएंगी। यह व्यवस्था दिन की पहली सेवा से लेकर सुबह 11 बजे तक मूल स्टेशन से खुलने वाली ट्रेनों पर लागू रहेगी, ताकि परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा मिल सके। हालांकि, अधिकांश एसी ईएमयू लोकल ट्रेनें रविवार के समयानुसार चलेंगी, लेकिन दो विशेष एसी ईएमयू सेवाएं अतिरिक्त रूप से संचालित की जाएंगी। इनमें 31638/31637 रानाघाट-सियालदह-रानाघाट एसी ईएमयू लोकल तथा 31847/31848 सियालदह-कृष्णानगर-सियालदह एसी ईएमयू लोकल शामिल हैं।

टाटा मोटर्स फाउंडेशन का ग्रामीण विकास मॉडल 200 गांवों तक पहुंचा. 1.15 लाख लोग हुए लाभान्वित

कोलकाता, समाज्ञा : टाटा मोटर्स फाउंडेशन ने अपने प्रमुख इंटीग्रेटेड विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम (आईवीडीपी) का विस्तार देशभर के करीब 200 गांवों तक कर दिया है। यह कार्यक्रम वर्तमान में 5 राज्यों की 103 ग्राम पंचायतों में संचालित हो रहा है और आदिवासी एवं कृषि-प्रधान क्षेत्रों में सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण विकास को बढ़ावा दे रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस पहल से 1.15 लाख से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। फाउंडेशन के अनुसार, करीब 20 करोड़ रुपये मूल्य की 50 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के साथ समन्वय स्थापित कर गांवों में प्रशासनिक और संस्थागत ढांचे को मजबूत किया गया है। वर्ष 2018 में महाराष्ट्र के पालघर जिले से शुरू हुआ यह कार्यक्रम अब राष्ट्रीय स्तर पर आत्मनिर्भर ग्रामीण विकास मॉडल के रूप में उभर रहा है। टाटा मोटर्स फाउंडेशन के सीईओ विनोद कुलकर्णी ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य समुदायों को आत्मनिर्भर बनाते हुए टिकाऊ ग्रामीण विकास सुनिश्चित करना है।

आईईटी इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड के 10वें संस्करण के लिए आवेदन शुरू. पुरस्कार राशि बढ़कर 20 लाख

कोलकाता, समाज्ञा : दुनिया की अग्रणी प्रोफेशनल इंजीनियरिंग संस्था इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (आईईटी) ने आईईटी इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड के 10वें संस्करण के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है। इस वर्ष स्कॉलरशिप की कुल पुरस्कार राशि दोगुनी कर 20 लाख कर दी गई है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक छात्र 15 जून 2026 तक आवेदन कर सकेंगे। आईईटी इंडिया स्कॉलरशिप अवार्ड देशभर के अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग छात्रों के लिए प्रमुख मंचों में से एक माना जाता है। पिछले एक दशक में इस कार्यक्रम ने उच्च छात्रों को पहचाना है, जिन्होंने इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के माध्यम से स्वास्थ्य, टिकाऊ खेती, कचरा प्रबंधन और सामाजिक चुनौतियों के समाधान प्रस्तुत किए हैं। स्कॉलरशिप के सलाहकार समिति अध्यक्ष अभिजीत चक्रवर्ती ने कहा कि यह पहल छात्रों को वास्तविक समस्याओं के व्यावहारिक समाधान विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन टेस्ट, क्षेत्रीय प्रस्तुति और राष्ट्रीय फाइनल शामिल होंगे।

मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार बेलूर मठ पहुंचे शुभेंदु, लिया आशीर्वाद



गिरफ्तारी के डर से अदिति-देवराज ने हाई कोर्ट में प्रग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी

कोलकाता, समाज्ञा : तृणमूल कांग्रेस की पूर्व विधायक अदिति मुंशी के पति पार्षद देवराज चक्रवर्ती मंगलवार की रात से ही अपनी गिरफ्तारी की खबरों की वजह से चर्चा में हैं। हालांकि, आखिरकार पता चला कि वह रिहा हो गए हैं। हालांकि, इस डर से कि उन्हें कभी भी आय से ज्यादा संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार किया जा सकता है, अदिति मुंशी और देवराज चक्रवर्ती ने हाई कोर्ट में प्रग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है। जस्टिस जॉय सेनुगुप्ता ने केस फाइल करने की इजाजत दे दी है। केस की सुनवाई आज होने की संभावना है। पता चला है कि आरोप यह है कि चुनावी हलफनामे में संपत्ति की सही रकम नहीं दिखाई गई थी। डर है कि इसी आरोप के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इसीलिए अदिति और देवराज ने इस बार एंटीसिपेटरी बेल अर्जी लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

बकाया डीए को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ बैठक

कोलकाता, समाज्ञा : संग्रामी संयुक्त मंच के सदस्य आगामी शनिवार, 30 मई को नवात्र में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक करने जा रहे हैं। मंच के संयोजकों में से एक भास्कर घोष ने यह जानकारी दी है। पता चला है कि इस बैठक में बकाया महंगाई भत्ते (डीए) पर चर्चा होगी। भास्कर घोष ने कहा कि इस बैठक में संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जाएगा।

भाटपाड़ा नगरपालिका में चेयरमैन समेत 29 पार्षदों ने दिया सामूहिक इस्तीफा

कोलकाता, समाज्ञा : कांचरापाड़ा, हालिशहर के बाद अब भाटपाड़ा। बैरकपुर औद्योगिक अंचल में तृणमूल की नगरपालिकाओं में बड़े पैमाने पर इस्तीफों की मांग तेज हो गई है। गुरुवार को भाटपाड़ा नगरपालिका के चेयरमैन समेत 29 पार्षदों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। सूत्रों का दावा है कि पिछले कुछ दिनों से असंतुष्ट पार्षदों के बीच कई बैठकें चल रही थीं। गुरुवार को वह गुस्सा सामने आ गया। भाटपाड़ा नगरपालिका के 35 वार्डों में से दो पार्षदों की मौत हो चुकी है। बाकी 33 में से चेयरमैन समेत 29 पार्षदों के एक साथ इस्तीफे की खबर राजनीतिक गलियारों में फैल गई।

राज्य सरकार ने किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 17 आईएस अधिकारियों का तबदला

कोलकाता, समाज्ञा : पश्चिम बंगाल सरकार के कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग ने राज्य में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 17 वरिष्ठ आईएस अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों की अधिसूचना जारी की है। राज्यपाल के आदेश पर जारी इस अधिसूचना के तहत कई नगर निगमों के कमिश्नर और जिलों के अतिरिक्त जिला

मजिस्ट्रेट (एडीएम) बदले गए हैं। अधिसूचना के अनुसार, सुजय सरकार (बैच 2010) को बिधाननगर नगर निगम के कमिश्नर पद से हटाकर अब इन्हें 'कमिश्नर ऑफ टेक्सटाइल्स एंड सरीकल्चर' बनाया गया है। साथ ही, इन्हें तंतुजा के एमडी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। नितिन सिंघानिया (बैच 2013) को केएमडीए के सीईओ पद

से ट्रांसफर कर इन्हें गृह एवं पर्वतीय मामलों विभाग में सीनियर स्पेशल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा, वह सर्वयेंद्रनाथ टैगोर सिविल सर्विसेज स्टडी सेंटर के कोर्स ऑफिसर और 'सेंटर ऑफ एक्सप्लेन इन पब्लिक मैनेजमेंट' के मेंबर सेक्रेटरी की अतिरिक्त जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। रवि अग्रवाल (बैच 2017) को पुलिसिया के एडीएम पद से पदोन्नत कर इन्हें बिधाननगर नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हिंद-तेल दत्त (बैच 2014) को आसनगढ़ तेल नगर निगम का नया कमिश्नर

बनाया गया है। इससे पहले वह ने-एजी सुभाष प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान में एसोसिएट प्रोफेसर थे। सुब्रत मलिक को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में आर्यभट्ट पद से हटाकर हावड़ा जिलाधिकारी (डीएम) एवं डीसी बनाया गया है। इसी तरह उसी विभाग में ओएसडी पद पर तैनात सुप्रतीति करणे को वहां से हटाकर दक्षिण दिनाजपुर जिले के डीएम एवं डीसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बुलबुल बाकची को वरिष्ठ उप सचिव, पीयूए विभाग से हटाकर एडीएम, बीरभूम बनाया गया है। डॉ.

हावड़ा, समाज्ञा : मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पदभार संभालने के बाद पहली बार ऐतिहासिक बेलूर मठ का दौरा किया। गुरुवार की सुबह वह रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के मुख्यालय पहुंचे। उनके इस दौरे को लेकर मठ परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और श्रद्धालुओं व आम लोगों में खासा उत्साह देखा गया। बेलूर मठ पहुंचकर मुख्यमंत्री सबसे पहले मुख्य श्रीरामकृष्ण मंदिर में गए। वहां उन्होंने श्रीरामकृष्ण परमहंस की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर पूजा की। इसके बाद, उन्होंने स्वामी विवेकानंद के स्मृति कक्ष में जाकर श्रद्धापूर्वक नमन किया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने स्वामी ब्रह्मानंद मंदिर और मां सारदा देवी मंदिर में भी जाकर श्रद्धा अर्पित की। मठ के शांत वातावरण में कुछ समय बिताने के बाद मुख्यमंत्री

बशीरहाट में भाजपा नेता के घर के बाहर बम और धमकी भरा खत मिला

कोलकाता, समाज्ञा : उत्तर 24 परगना जिले में गुरुवार की सुबह एक भाजपा नेता के घर के बाहर से एक देसी बम और एक धमकी भरा खत बरामद हुआ, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह घटना बशीरहाट थाना अंतर्गत शासिना गांव में हुई, जहां भाजपा बृह्म अध्यक्ष अनिल बरन मल्लिक रहते हैं। आरोप है कि बरनमल्लिक ने रात के अंधेरे का फायदा उठाया और भाजपा से पहले उनके घर के प्रवेश द्वार पर दो देसी बम रख दिए। वहां मामला सुबह में तब सामने आया जब मल्लिक ने दरवाजा खोला और उन्हें वे विस्फोटक दिखाई दिए। जैसे ही इस मामले



की सूचना अन्य लोगों को हुई, इलाके में तनाव फैल गया और ग्रामीण मौके पर जमा हो गए और पुलिस को सूचना दी। पुलिसकर्मी और क्षेत्र में तैनात केंद्रीय बल तुरंत मौके पर पहुंचे और विस्फोटकों को सुरक्षित रूप से हटा दिया। बालकनी की गिरल से बंधा एक धमकी भरा पत्र और बोलतलें भी मिलीं, जो भाजपा नेता के अनुसार, पहले भी डराने-धमकाने

मेयर परिषद की बैठक बाद अब केएमसी का मासिक अधिवेशन स्थगित

कोलकाता, समाज्ञा : हालिया संपन्न विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के करारी हार के बाद भाजपा ने राज्य पर कब्जा कर लिया है। राजनीतिक उथल-पुथल के कारण कोलकाता नगर निगम (केएमसी) में काफी तनाव है। ऐसे में नगर निगम का मासिक अधिवेशन स्थगित कर दिया गया है। नगर निगम सचिव ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन में इस फैसले की घोषणा की। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि शुक्रवार का नगर निगम अधिवेशन टाल दिया गया है। नोटिफिकेशन में बैठक टालने का कोई कारण नहीं बताया गया है। अभी यह साफ नहीं है कि बैठक दोबारा कब होगी। बता दें कि इससे पहले कोलकाता नगर निगम की तय



मेयर काउंसिल की बैठक रद्द कर दी गई थी। यह बैठक सोमवार, 18 मई को होनी थी। लेकिन, आखिरी समय में इसे रद्द कर दिया गया। नगर निगम सूत्रों के मुताबिक, नगर निगम कमिश्नर स्मिता पांडे बैठक के लिए समय नहीं दे पाएंगी। इसलिए बैठक रद्द कर दी गई। इसके बाद, मेयर फिरहाद हकीम ने भी बैठक रद्द करने की घोषणा की। नई तारीख बाद में तय की जाएगी। उस समय फिर से समय की घोषणा की जाएगी।

राज्य ने केएमसी सचिव पद में किया फेरबदल

राज्य सरकार कोलकाता नगर निगम (केएमसी) को लेकर कड़े फैसले ले रही है। इस बार, सचिव के पद पर फेरबदल किया गया है। अभी तक स्वप्न कुमार कुंडू केएमसी के सचिव थे। उन्हें ओएसडी (स्टेट गजेटियर्स) बनाकर भेजा गया है। उनकी जगह किशोर कुमार बिस्वास को केएमसी का सचिव बनाया गया है। वे पूर्व बर्दवान जिला परिषद के डिप्टी सचिव थे। ये दोनों डब्ल्यूबीसीएस एजीक्यूटिव ऑफिसर हैं।

हावड़ा स्टेशन पर संदिग्ध पैकेट में लगी आग, सीसीटीवी में कैद हुआ युवक

मिथिला एक्सप्रेस घटना से जुड़ाव की जांच हावड़ा : हावड़ा स्टेशन के कैब रोड इलाके में एक संदिग्ध पैकेट में आग लगने की घटना के बाद आरपीएफ और रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। यह घटना 19 मई को 13021 हावड़ा-रक्सौल मिथिला एक्सप्रेस के एक जनरल कोच से धुआं निकलने की घटना से करीब एक घंटे पहले की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, मिथिला एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से रवाना होने की तैयारी में थी, तभी एक जनरल डिब्बे से धुआं उठता देखा गया। घटना के बाद यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। सूचना मिलने पर आरपीएफ और रेलवे अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। एहतियात के

तौर पर प्रभावित कोच को ट्रेन से अलग कर दूसरे डिब्बे को जोड़ा गया, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। जांच के दौरान पुराने कैब रोड इलाके के सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध युवक टिकट काउंटर के पास पैकेट फेंकते दिखाई दिया। कुछ देर बाद पैकेट में आग लग गई। फुटेज में युवक को दूर खड़े होकर घटना पर नजर रखते भी देखा गया। पूर्व रेलवे हावड़ा मंडल के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त चोखा चुबरी ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छह विशेष टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं। प्राथमिक जांच में घटनास्थल से पेट्रोल जैसी ज्व-लनशील पदार्थ की गंध मिलने की पुष्टि हुई है। फिलहाल, मामले की गहन जांच जारी है।

चौथी बार बेटे होने पर नवजात की हत्या, शव नाले में फेंकने वाले दंपति को उम्रकैद

हुगली : लगतार चौथी बार बेटे पैदा होने के बाद नवजात बच्ची की हत्या कर शव नाले में फेंकने के मामले में हुगली के एक दंपति को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। चूंछुड़ा की तृतीय जिला एवं सत्र अदालत ने न्यायाधीश कोस्तभ मुखोपाध्याय ने गुरुवार को आरोपी माता-पिता पूर्णिमा टुडू और नारायण टुडू को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त छह महीने की जेल काटनी होगी।

मामला हुगली जिले के मानुसमारी गांव का है। जानकारी के अनुसार, 24 दिसंबर 2020 को पूर्णिमा टुडू ने अपने घर में चौथी बार एक बेटे को जन्म दिया था। आरोप है कि उसी दिन पति नारायण टुडू के साथ मिलकर उसने नवजात बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद सबूत मिटाने के लिए बच्ची के शव को एक नालयान बैग में भरकर घर के पास स्थित मानुसमारी नाले में फेंक दिया गया। बाद में नाले से बच्ची का शव बरामद हुआ। पड़ोसी गणेश मुर्मु ने पूर्णिमा और नारायण के खिलाफ हत्या की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद पांडुआ थाने के पुलिस अधिकारी बुद्धदेव सरकार ने मामले की जांच शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि नवजात की हत्या गला दबाकर की गई थी। जांच के दौरान पुलिस ने दंपति को गिरफ्तार किया, लेकिन शव मिलने के बाद भी दोनों ने बच्ची को अपना संतान मानने से इनकार कर दिया।

इसके बाद अदालत के निर्देश पर डीएनए परीक्षण कराया गया। डीएनए रिपोर्ट में साबित हो गया कि मृत नवजात पूर्णिमा और नारायण की ही बेटे थी।

मामले में कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सभी साक्ष्यों, गवाहों और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने बुधवार को दोनों को दोषी करार दिया था। इसके बाद गुरुवार को सजा सुनाई गई। हुगली जिले के मुख्य सरकारी वकील शंकर गंगोपाध्याय ने बताया कि 24 दिसंबर 2020 को पांडुआ थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि डीएनए जांच इस मामले का सबसे महत्वपूर्ण सबूत साबित हुई, जिसके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

डानकुनी के तृणमूल पार्षद सूर्य दे गिरफ्तार

हुगली : डानकुनी नगरपालिका के वार्ड संख्या 18 के पार्षद और तृणमूल नेता सूर्य दे को डानकुनी थाने की पुलिस ने गुरुवार तड़के गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार उन्हें गुरुवार को श्रीरामपुर अदालत में पेश किया जाएगा। बताया गया है कि एक व्यक्ति के साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दर्ज एक पुराने मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि यह घटना 2021 विधानसभा चुनाव के बाद की है, लेकिन आरोपी के डर से पीड़ित उस समय थाने में लिखित शिकायत दर्ज नहीं करा सके थे। बाद में पीड़ित परिस्थितियां बदलने के बाद पीड़ित ने दोबारा शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के बाद गुरुवार तड़के पुलिस ने डानकुनी स्थित उनके



आवास से उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि हाल ही में एसआईआर की अंतिम सूची में अनाम नाम मृत घोषित किए जाने को लेकर सूर्य दे ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। बाद में उन पर संबंधित बीएलओ के साथ मिलीभगत कर खुद ही अपना नाम मृतकों की सूची में शामिल करवाने का आरोप लगा था। इस घटना को लेकर राजनीतिक हलकों में भी काफी चर्चा हुई थी।

www.samagya.in

समाज्ञा

NEWS PAPER ADVERTISING SOLUTION

- MATRIMONIAL
- EDUCATION
- OBITUARY
- PROPERTY
- NAME CHANGE
- REMEMBRANCE
- RECRUITMENT
- PUBLIC NOTICE
- DISPLAY

TO AD IN SAMAGYA PLEASE CONTACT

samagyaadvt@gmail.com | samagya.in

230, C. R. Ave, 3rd Floor, Kolkata-700 006, Contact : 7044444522, 7044444527

नौसेना प्रमुख के रूप में सेवानिवृत्त होने से पहले एडमिरल त्रिपाठी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की



नयी दिल्ली : निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। एडमिरल त्रिपाठी 31 मई को सेवानिवृत्त होंगे। राष्ट्रपति कार्यालय ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को आभले नौसेना प्रमुख के रूप में नामित किया गया है।

तमिलनाडु: राज्यपाल ने शपथ के दौरान नेताओं के नाम लेने पर कांग्रेस सदस्य को टोका

चेन्नई : तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर ने बृहस्पतिवार को मंत्री पद की शपथ लें रहे कांग्रेस नेता एच राजेश कुमार को टोकते हुए उन्हें लिखित शपथ ही पढ़ने को कहा। कांग्रेस विधायक दल के नेता राजेश कुमार किच्छोर से विधायक हैं और वह आज शपथ ग्रहण करने वाले मंत्रियों में शामिल रहे। यहां लोक भवन में राज्य के मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के दौरान जब कुमार लिखित शपथ पढ़ रहे थे, तभी अचानक वह कांग्रेस नेताओं का मराजा, राजीव गांधी और राहुल गांधी की प्रशंसा में नारे लगाने लगे। इसके बाद राज्यपाल ने टोकते हुए कुमार से कहा, यह आपकी शपथ का हिस्सा नहीं है। कुमार के शपथ लेने के कुछ ही मिनट बाद सलेम दक्षिण से टीवीके विधायक ए विजय तमिलन पार्थिवन ने मंत्री पद की शपथ लेने के बाद मंच पर उच्च-स्थिति पार्टी नेता और मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की प्रशंसा करते हुए नारे लगाए। श्रीपेरंबुदूर से टीवीके सदस्य थेनारासु ने भी मंत्री के रूप में अपनी शपथ लेते हुए कहा कि वह पार्टी और उसके नेता के प्रति निष्ठावान रहेंगे।

माँस्को में ड्रोन हमले में मारे गए ओडिशा के श्रमिक का शव लाया गया

भुवनेश्वर : रूस की राजधानी माँस्को में ड्रोन हमले में मारे गए ओडिशा के एक मजदूर का शव बृहस्पतिवार को इस राज्य में लाया गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि गंजांग जिले के चिकीटी ब्लॉक स्थित मधाबंधा गांव का निवासी अंजानामा रामया (30) रूस की एक कंपनी में काम करता था। 17 मई को यूक्रेन द्वारा रूस की राजधानी माँस्को पर किए गए ड्रोन हमले में उसकी मौत हो गई। उसकी मौत की खबर मिलने के बाद परिवार के सदस्यों ने राज्य सरकार से शव को वापस लेने की अपील की थी। अधिकारियों ने बताया कि इस अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय की सहायता से शव को वापस लेने की व्यवस्था की। ओडिशा परिवार के विशेष कार्य अधिकारी प्रीतीश पांडा ने भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर शव को प्राप्त किया। पांडा ने कहा, "श्रमिक के शव को गंजांग स्थित उसके पैतृक गांव ले जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।"

चुनाव में भ्रष्ट आचरण का आरोप : अदालत ने टीवीके नेता विजय को नोटिस जारी किया

चेन्नई : मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को तमिलनाडु वेदी कर्णम (टीवीके) के संस्थापक और मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय तथा अन्य को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक याचिका पर जारी किया गया है, जिसमें निर्वाचन आयोग को यह निर्देश देने की मांग की गई है कि वह तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान कथित भ्रष्ट आचरण की जांच करे, जिसमें मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बच्चों के उपयोग जैसे आरोप शामिल हैं। मद्रास उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को टीवीके के संस्थापक और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय तथा अन्य को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति जी आर स्वामीनाथन और न्यायमूर्ति वी. लक्ष्मीनारायणन की अवरकाशकालीन पीठ ने निर्वाचन आयोग, तमिलनाडु के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, द्रुमक अध्यक्ष एम के स्टालिन और पलायनसुमा को भी नोटिस जारी किया। यह जनहित याचिका कडलूर जिले के अधिवक्ता एल वासुकी द्वारा दायर की गई है। पीठ ने मामले की आगूली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की है।

देश के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी, उग्र के बांदा में सबसे अधिक 47.6 डिग्री तापमान

नयी दिल्ली : देश के कई राज्यों में बृहस्पतिवार को भी भीषण गर्मी और लू का कहर जारी रहा। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ देश का सबसे गर्म स्थान रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में भी गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। दिल्ली रिज क्षेत्र में अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आयानगर में 44.5 डिग्री, पालम और लोधी रोड में



44.3 डिग्री तथा सफदरजंग में 43.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली में इस मौसम का पहला लू का मामला भी सामने आया, जहां पश्चिम बंगाल का 24 वर्षीय छात्र गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश में लगातार

गंभीर बने हुए हैं। पंजाब के फरीदकोट में 45.9 डिग्री और हरियाणा के सिरसा में 45.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में परा 44.2 डिग्री तक पहुंच गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी तापमान सामान्य से कई डिग्री अधिक दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने हिमाचल के कई जिलों में बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं, उत्तराखंड में बच्चों, बुजुर्गों और बाहर काम करने वाले श्रमिकों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

बांद्रा में अतिक्रमण हटाने के दौरान पुलिस पर पथराव करने वालों को गिरफ्तार किया गया : फडणवीस

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बृहस्पतिवार को कहा कि मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में अतिक्रमण हटाने के लिए चलाए जा रहे ध्वस्तिकरण अभियान के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "बुधवार को अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव किया। स्थिति को नियंत्रण में लाया गया और पथरावबाजी में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया।" मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ने हमले के बाद कार्रवाई की। बंबई उच्च न्यायालय



के आदेश के बाद पश्चिमी रेलवे के अंतर्गत आने वाले बांद्रा रेलवे स्टेशन के पूर्वी हिस्से से सटे गरीब नगर में अतिक्रमण रोधी अभियान चलाया गया और करीब 500 अवैध ढांचे ध्वस्त कर दिये गए। पश्चिमी रेलवे ने कहा है कि वह रेलवे बुनियादी ढांचे के विकास के लिए अनधिकृत से उसकी जमीन पर कब्जा कर बनाई गई झुग्गियों को हटाना चाहता था। अधिकारियों द्वारा बुधवार को कथित तौर पर एक अवैध मस्जिद को ध्वस्त करने के अभियान के दौरान हुई पथरावबाजी में तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए। हिंसा के संघर्ष में कम से कम 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने विधायक के रूप में शपथ ली

गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बृहस्पतिवार को नयी विधानसभा के पहले दिन विधायक के रूप में शपथ ली। असम विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष चंद्र मोहन पटवारी ने शर्मा को 16वीं विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाई। शर्मा ने असमिया भाषा में शपथ ली। अस्थायी अध्यक्ष पटवारी ने कहा, सभी सदस्य अपनी इच्छानुसार किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में शपथ ले सकते हैं। वे अपनी शपथ की प्रतियां विधानसभा कार्यालय में जमा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री के बाद, अन्य विधायकों ने भी असमिया, बांग्ला, बोडो और संस्कृत जैसी विभिन्न भाषाओं में शपथ ली। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) ने राज्य विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 126 सदस्यीय सदन में 102 सीटों पर जीत दर्ज की। इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा), असम गण परिषद (एजीपी) और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) शामिल हैं। भाजपा ने अकेले 82 सीटें जीतीं, जबकि एजीपी और बीपीएफ ने



10-10 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं, छह दलों के विपक्षी गठबंधन का हिस्सा रही कांग्रेस और रायजोर दल ने क्रमशः 19 और दो सीटें जीतीं। इसके अलावा अकेले चुनावी मैदान में उतरने वाले ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) ने दो और वृणमूल कांग्रेस ने एक सीट पर जीत हासिल की।

दिल्ली में राशन कार्ड के लिए पात्र होने की आय सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये सालाना की जाएगी: गुमा

नयी दिल्ली : मुख्यमंत्री रेखा गुमा ने बृहस्पतिवार को कहा कि दिल्ली सरकार ने सात लाख से अधिक राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं और नए राशन कार्ड जारी करने के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष करने की योजना है। गुमा ने यहां पत्रकारों से कहा कि सरकार ने लगभग 7.72 लाख अमान्य राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं और ऑनलाइन ए आवेदन आमंत्रित किए हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली में पिछले 13 वर्षों में कोई राशन कार्ड जारी नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा, गहन ऑडिट के बाद, सरकार ने आय मानदंड को पूरा न करने वाले 1.44 लाख लाभार्थियों, राशन कार्ड न करने वाले 35,800 लाभार्थियों, मृत पाए गए 29,580 लाभार्थियों को हटा दिया, जबकि



23,394 राशन कार्ड 'डुप्लिकेट' पाए गए। फिलहाल, दिल्ली में राशन कार्ड के लिए पात्र होने की आय सीमा 1.2 लाख रुपये प्रति वर्ष निर्धारित है। गुमा ने कहा कि आय पात्रता में बढ़ोतरी जरूरतमंद लोगों को अधिकतम संख्या को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। गुमा ने कहा, गरीब और मध्यम वर्ग के

परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में लाने के लिए दिल्ली खाद्य सुरक्षा नियम, 2026 के तहत राशन कार्ड के लिए वार्षिक पारिवारिक आय पात्रता सीमा पहले ही एक लाख रुपये से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये कर दी गई है। उन्होंने बताया कि अगली कैबिनेट बैठक में इस सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए राशन कार्डों के लिए तथा परिवार के सदस्यों को जोड़ने के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 मई, 2026 से ई-जिला पोर्टल के माध्यम से शुरू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि नए राशन कार्डों के लिए 3,72,367 आवेदन और परिवार के सदस्यों को शामिल करने के लिए 99,501 आवेदन वर्तमान में लंबित हैं।

दिल्ली में तीन दिवसीय परिवहन हड़ताल शुरू, कई इलाकों में यात्रियों ने परेशान होने की शिकायत की

नयी दिल्ली : दिल्ली सरकार की ओर से वाणिज्यिक वाहनों पर पर्यावरण मुआवजा उपकर लगाए जाने और सीएनजी की कीमतों में वृद्धि के विरोध में ट्रांसपोर्ट और टैक्सी संगठनों ने बृहस्पतिवार को दिल्ली-एनसीआर में तीन दिवसीय हड़ताल की शुरुआत की जिसकी वजह से कई इलाकों में यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ट्रांसपोर्ट और टैक्सी संगठनों के मुताबिक उनकी हड़ताल 23 मई तक जारी रहेगी। राष्ट्रीय राजधानी के कुछ सबसे व्यस्त स्थानों, जिनमें नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन, आंध्र विहार, मंडी हाउस मेट्रो और अन्य स्थान शामिल हैं, पर यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हड़ताल के तहत संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में ट्रक खड़े रहे। एक यात्री ने बताया, "हमने घर जाने के लिए टैक्सी बुक करने की

कोशिश की, लेकिन प्रतीक्षा समय सामान्य से अधिक था, और स्टेशन पर ऑटो-रिक्शा भी बहुत कम उपलब्ध थे। टैक्सी बुक करने का शुल्क भी अधिक था।" ट्रक चालकों, निजी बसों, टैक्सी और मैक्सी केब संचालकों की सर्वोच्च संस्था 'ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस' (एआईएमटीसी) ने इस हड़ताल का आह्वान किया है। एआईएमटीसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरीश सभवाल ने 'पीटीआई वीडियो' से कहा, "हम प्रदूषण कम करने के प्रयासों का समर्थन करते हैं, लेकिन पिछले 10-12 वर्षों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर के माध्यम से लगभग 1,500 करोड़ रुपये एकत्र करने के बावजूद, सरकार ने परिवहन कल्याण, पार्किंग, सड़कों या प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए इस धन का उचित उपयोग नहीं किया है।"

यदि आरोपी को कोई आपत्ति न हो तो न्यायालय राजद्रोह के मुकदमे चला सकते हैं : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि अदालतें राजद्रोह से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धारा 124ए से जुड़े मुकदमों की सुनवाई कर सकती हैं, यदि आरोपी को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। भारत के प्रधान न्यायाधीश सुर्यकांत, न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ ने राजद्रोह से संबंधित एक मामले में 17 वर्षों से लंबित एक आदेश को याचिका पर सुनवाई करते हुए यह स्पष्टीकरण दिया। आरोपी द्वारा दायर अपील पत्रादेश उच्च न्यायालय में लंबित है। पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि यदि उसकी

आपराधिक अपील की पूरी सुनवाई की जाए, जिसमें धारा 124ए के तहत आरोप भी शामिल हो, तो उसे कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में, हम स्पष्ट करते हैं... कि जहां भी आरोपी को मुकदमे, अपील या किसी अन्य कार्यवाही के खिलाफ कोई आपत्ति नहीं है, जिसमें उस पर धारा 124ए आईपीसी के तहत भी आरोप पत्र दाखिल किया गया है, तो न्यायालयों को ऐसे मामलों में गुण-दोष और कानून के अनुसार निर्णय लेने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए।" उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ता की अपील पर सुनवाई करने और गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

आदिवासी अपराधी नहीं, बल्कि भारत के गौरव हैं: वनवासी कल्याण आश्रम के प्रमुख

नयी दिल्ली : अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने बृहस्पतिवार को देश में आदिवासियों के बारे में 'विकृत' औपनिवेशिक धारणाओं को सुधारने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि वे भारत के गौरव और इसकी संस्कृति के रक्षक हैं, न कि अपराधी। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासकों ने उनके अपराधी होने की छवि पेश की थी। सिंह ने 'पीटीआई-वीडियो' के साथ साक्षात्कार में कहा कि वनवासी कल्याण आश्रम से संबद्ध जनजाति सुरक्षा मंच, आदिवासी प्रतीक बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के अवसर पर भारत के 'वनवासी' समुदाय के बारे

में दुनिया को एक सकारात्मक संदेश देने के लिए रिवार को यहां आदिवासियों का एक विशाल सांस्कृतिक सम्मेलन आयोजित कर रहा है। उन्होंने कहा, "अब तक आदिवासी समुदायों के बारे में जो कुछ भी लिखा और पढ़ाया गया है, उसका अधिकांश भाग ब्रिटिश विद्वानों और औपनिवेशिक विचारकों द्वारा लिखा गया है। उन्होंने आदिवासी समाज को सही ढंग से प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने आदिवासियों को अपराधी या पिछड़े लोग के रूप में पेश किया। लेकिन आदिवासी समाज का सच्चा इतिहास इससे बहुत अलग है। आदिवासी समुदायों ने इस देश और इसकी

संस्कृति में बहुत बड़ा योगदान दिया है।" सिंह ने कहा, "रामायण काल हो, महाभारत काल हो, मुगल युग हो या ब्रिटिश शासन-आदिवासी समुदायों ने अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की। यही आदिवासी समाज का आत्मसम्मान है।" उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों की संस्कृति, परंपराएं, जीवनशैली और लोक कलाएं देश के लिए गर्व का विषय हैं, इसलिए, वनवासी कल्याण आश्रम यह संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है कि आदिवासी समाज राष्ट्र का गौरव और इसकी संस्कृति का रक्षक है।

राजनाथ ने सियोल में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया

नयी दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में कोरियाई युद्ध की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप में शांति और मानवीय सहायता के लिए भारत के योगदान को स्थायी विरासत बताया। रक्षा मंत्री ने दक्षिण कोरिया के देशभक्ति एवं पूर्व सैनिक मामलों के मंत्री क्योव ओह-युल के साथ इमजिंगक पार्क में बने इस स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। यह स्मारक भारतीय सेना की '60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस' और 'कस्टोडियन फोर्स ऑफ इंडिया' (सीएफआई) की बहादुरी, बलिदान और मानवीय सेवाओं को समर्पित है। अपने



संबंधन में राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और दक्षिण कोरिया का साझा इतिहास तथा सैनिकों का बलिदान दोनों देशों की विशेष रणनीतिक साझेदारी की मजबूत नींव है। उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों की भूमिका को याद करना दोनों देशों के बीच आपसी समझ और ऐतिहासिक संबंधों को और मजबूत बनाता है। दक्षिण कोरिया के मंत्री क्योव ओह-युल ने कोरियाई युद्ध के दौरान भारत की भूमिका की

सराहना करते हुए भारतीय सैनिकों के मानवीय दृष्टिकोण और बलिदान को अविस्मरणीय बताया। दोनों देशों के मंत्रियों ने युद्ध के पूर्व सैनिकों के सम्मान और सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, लेफ्टिनेंट कर्नल डॉ. ए.जी. रंजराज के नेतृत्व वाली 60 पैरा फील्ड एम्बुलेंस के कटिन परिस्थितियों में हजारों घायल सैनिकों और नागरिकों का उपचार किया। उनकी बहादुरी और सेवा भावना के कारण उन्हें मैरून एंजलस कहा गया। युद्धविराम के बाद भारत ने 'न्यूट्रल नेशंस रिप्रेटिएशन कमीशन' के तहत लगभग 22 हजार युद्धबंदियों की सुरक्षित वापसी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

भारत को समृद्ध बनाने का जो सपना पापा ने देखा था उसे मैं साकार करूंगा: राहुल

नयी दिल्ली : कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और कहा कि उनके पिता ने भारत को समृद्ध बनाने का जो सपना देखा था उसे वह साकार करेगा। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा सहित पार्टी के कई नेताओं ने राजीव गांधी के स्मारक 'वीर भूमि' जवहर उन्हे श्रद्धांजलि अर्पित की। राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी के साथ अपने बचपन की एक तस्वीर साझा की और कहा, "पापा, आपने जिस कुशल, समृद्ध और मजबूत भारत का

प्रधानमंत्री के उपहार: इटली की प्रधानमंत्री को भेंट किया मूंग रेशम स्टॉल

नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल ही में संपन्न अपनी पांच देशों की यात्रा के दौरान विभिन्न देशों के नेताओं को भारत की समृद्ध कला, संस्कृति और हस्तशिल्प से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए। इटली की प्रधानमंत्री जर्जिना मेलेनी को असम का प्रसिद्ध मूंग रेशम दुपट्टा और 'मेलोडी' टॉफी भेंट की गई। मेलेनी ने सोशल मीडिया पर टॉफी को बहुत बढ़िया बताया। मूंग रेशम अपने प्राकृतिक सुनहरे रंग और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध है। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटेन को मछली की आकृति वाली मधुबनी चित्रकला भेंट की गई, जबकि स्वीडन के प्रधानमंत्री उर्फ क्रिस्टर्सेन को लदाखी शुद्ध ऊन का दुपट्टा दिया गया। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर



स्टोर को सूखे ऑर्किड से बनी कलाकृतियां और नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम को ओडिशा की प्रसिद्ध तारकासी कला से निर्मित चांदी की पाल वाली नाव का मॉडल भेंट किया गया। इसके अलावा, विभिन्न देशों के नेताओं को जयपुर की नीली मिट्टी कला, मीनाकारी-कुंडस आभूषण तथा बिदरी पच्चीकारी जैसे भारतीय हस्तशिल्प कृतियां भी उपहार में दी गईं।

एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' 300 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज होगी

मुंबई : भुवनेश्वर का एनिमेशन स्टूडियो 'एली एनिमेशंस' अपनी लोकप्रिय टेलीविजन श्रृंखला जय जगन्नाथ को अब बड़े पैमाने पर लाने जा रहा है। स्टूडियो इस सिलसिले में महाप्रभु जगन्नाथ नाम से एक एनिमेटेड फीचर फिल्म बना रहा है। एक विवाचित्त के अनुसार, स्टूडियो ने मल्टीप्लेस्क श्रृंखला 'सिनेपोलिस' के सहयोग से इस फिल्म को हिंदी, उड़िया और तेलुगु भाषाओं में देश भर के 300 से अधिक सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बनाई है। इससे पहले जय जगन्नाथ श्रृंखला का प्रसारण 'पोंगो' चैनल पर हुआ था, जिसे शंकाओं ने काफी संदेह किया था। यह फीचर फिल्म भगवान जगन्नाथ की पौराणिक कथाओं पर आधारित होगी और इसमें एनिमेशन के साथ भक्तिपूर्ण कहानियों का मिश्रण होगा। 'एली एनिमेशंस' के संस्थापक और मुख्य कार्यवाहक अधिकारी (सीईओ) दुर्गा प्रसाद दलाल ने कहा कि टेलीविजन श्रृंखला की जबरदस्त सफलता के बाद इसे बड़े पैमाने पर लाना एक स्वाभाविक कदम था।

कांथा कढ़ाई शिल्पी तृप्ति मुखर्जी को पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा

नयी दिल्ली : पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध कांथा कढ़ाई शिल्पी तृप्ति मुखर्जी को पारंपरिक हस्तशिल्प कला के संरक्षण और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में योगदान के लिए 25 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। कांथा कढ़ाई में 37 वर्षों से अधिक का अनुभव रखने वाली तृप्ति मुखर्जी ने कम उम्र में अपनी मां से प्रेरणा लेकर इस कला को अपनाया। उन्होंने पश्चिम बंगाल के सूरी में एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया, जहां महिलाओं को कांथा कढ़ाई, साडी डिजाइन, वॉल हैंगिंग, बेडशीट, स्टोल और दुपट्टे तैयार करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। उनके प्रशिक्षण से जुड़ी कई महिलाएं आज सरकारी मेलों और प्रदर्शनों में अपने उत्पाद बेचकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। मुखर्जी ने विदेशों में भी भारतीय हस्तशिल्प का प्रतिनिधित्व किया है। उन्हें इससे पहले राष्ट्रीय पुरस्कार, शिल्प गुरु सम्मान और बंगश्री पुरस्कार भी मिल चुका है।

इंजेक्शन से लगाए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पादों की कानून के तहत अनुमति नहीं है : सीडीएससीओ

नयी दिल्ली : केंद्रीय औषधि नियामक ने स्पष्ट किया है कि इंजेक्शन के रूप में आपूर्ति किए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पाद कानून के तहत 'कॉस्मेटिक्स' की परिभाषा में नहीं आते हैं और उपभोक्ताओं या पेशेवरों द्वारा इनका उपयोग करने की अनुमति नहीं है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की यह सलाह ऐसे समय में आई है जब देश भर के ब्यूटी क्लीनिक और वेलेनेस सेंटर में इंजेक्शन द्वारा की जाने वाली सौंदर्य संबंधी प्रक्रियाओं को 'कॉस्मेटिक उपचार' के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और इनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। एक सूत्र ने बताया कि यह स्पष्टीकरण उपचार के उद्देश्य से कॉस्मेटिक उत्पादों के दुरुपयोग को रोकने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से है, खासकर जब शहरी क्षेत्रों में और सोशल मीडिया प्रचार के माध्यम से ऐसी प्रक्रियाएं लोकप्रियता हासिल कर रही हैं। नियामक ने 18 मई को जारी सार्वजनिक सूचना में कहा है कि सौंदर्य प्रसाधनों का उद्देश्य केवल बाहरी तौर पर इत्तेमाल करने के लिए है, न कि इंजेक्शन द्वारा। नोटिस में कहा गया है, "इंजेक्शन के रूप में आपूर्ति किए जाने वाले उत्पाद सौंदर्य प्रसाधनों की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं। किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद को उपभोक्ता/पेशेवर/सौंदर्य क्लिनिक द्वारा इंजेक्शन के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है।"

डीआरआई ने 120 करोड़ रुपये मूल्य की तीन लाख ई-सिगरेट जन्त की

नयी दिल्ली : राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तस्करों गिरोह के खिलाफ चलाए गए अभियान के दौरान 120 करोड़ रुपये मूल्य की तीन लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और 'वेप' जन्त की। वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। मंत्रालय के बयान के अनुसार प्रतिबंधित ई-सिगरेट हर मामले में चीन से मंगाई गई थीं और उन्हें फर्नीचर तथा धातु की कुर्सियों के पुर्जों जैसी वस्तुओं के बीच छिपाकर आयात किया गया था। विशेष खुफिया सूचना के आधार पर डीआरआई ने कई संदिग्ध आयात खेपों की पहचान की, उनका पता लगाया और उन्हें रोका। इन खेपों को सीमा शुल्क जांच से बचने के लिए गलत तरीके से घोषित किया गया था। विस्तृत जांच के परिणामस्वरूप विभिन्न ब्रांड, फ्लेवर और विशिष्टताओं वाली लगभग तीन लाख इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट/वेप जन्त की गई, जिनकी कीमत 120 करोड़ रुपये से अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और सभी इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन वितरण प्रणालियां भारत में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध (उत्पादन, निर्यात, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विनाशन) अधिनियम, 2019 के तहत प्रतिबंधित हैं, जिसे जन स्वास्थ्य के हित में और लोगों को नुकसान से बचाने के लिए लागू किया गया है।

भारत को समृद्ध बनाने का जो सपना पापा ने देखा था उसे मैं साकार करूंगा: राहुल



सपना देखा था, उसे साकार करने की जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। आपकी सोच, आपके संस्कार और आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी।" खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "भारत के एक संपूर्ण, जिन्होंने देश भर में लाखों लोगों में आशा और आकांक्षा को प्रेरित किया, पूर्व प्रधानमंत्री और 'भारत

जेप्टो की जुलाई में 11,000 करोड़ रुपये का आईपीओ लाने की योजना

नयी दिल्ली : फटाफट सामान की आपूर्ति करने वाले कंपनी जेप्टो जुलाई में 11,000 करोड़ रुपये का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की योजना बना रही है। मामले से जुड़े लोगों ने बहस्पतिवार को यह जानकारी दी। यदि सूचीबद्धता की योजना पूरी होती है तो जेप्टो शेयर बाजार में पहले से सूचीबद्ध प्रतिस्पर्धी जोमैटो और स्विगी की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। जेप्टो को इस महीने की शुरुआत में भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) से आईपीओ लाने की मंजूरी मिली थी। अब कंपनी नियामक के पास संशोधित आईपीओ दस्तावेज (यूडीआरएचपी) दाखिल करने की तैयारी में है। जेप्टो ने दिसंबर, 2025 में गोपनीय मार्ग के जरिये आईपीओ दस्तावेज दाखिल किए थे। मामले से परिचित लोगों ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि आदित पालिचा और कैवल्य वोहरा द्वारा स्थापित जेप्टो 31 जुलाई से पहले शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने का लक्ष्य बना रही है।

पंजाब एंड सिंध बैंक एपीवाई वार्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित

नयी दिल्ली : पंजाब एंड सिंध बैंक को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एपीएफआरडीए से एपीवाई वार्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। यह पुरस्कार बुधवार को पेंशन कोष विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के एक कार्यक्रम में वित्तीय सेवा सचिव एम नागराजू ने पंजाब एंड सिंध बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्वर्ण कुमार साहा को प्रदान किया। बयान के अनुसार, यह सम्मान अटल पेंशन योजना को व्यापक स्तर पर अपनाने के जरिए देशभर में वित्तीय समावेश को मजबूत करने और सामाजिक सुरक्षा पहल को बढ़ावा देने के प्रति बैंक की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बैंक ने कहा कि वह लगातार वंचित और असंगठित क्षेत्रों तक पेंशन दायरा का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहा है, ताकि प्रत्येक नागरिक को वित्तीय सुरक्षा और बेहतर भविष्य सुनिश्चित किया जा सके।

अगले महीने व्यापार वार्ता के लिए भारत आ सकता है अमेरिकी दल : गोयल

नयी दिल्ली : वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बहस्पतिवार को कहा कि व्यापार वार्ता के लिए अमेरिकी दल अगले महीने भारत आ सकता है। अंतरिम समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने और व्यापक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) के तहत वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय पक्ष ने अप्रैल में वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकी समक्षों के साथ आमने-सामने बैठक की थी। यह पूछे जाने पर कि क्या बीटीए के लिए अमेरिका के मुख्य वार्ताकार, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ आगे तो गोयल ने कहा, 'वह उनके साथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके अगले महीने आने की योजना है।' रूबियो 23 मई से भारत की चार दिवसीय यात्रा पर आएंगे जिसका उद्देश्य व्यापार, रक्षा एवं ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाना है। यह उनकी भारत की पहली यात्रा होगी। भारत और अमेरिका के सात फरवरी को एक संयुक्त बयान जारी कर अंतरिम व्यापार समझौते के लिए एक रूपरेखा को अंतिम रूप दिया था। हालांकि, अमेरिका के सर्वोच्च



न्यायालय के एक फैसले ने सभी जवाबी शुल्कों को निरस्त कर दिया जिसे अमेरिकी प्रशासन साझेदार देशों के साथ व्यापार समझौते करने के लिए एक साधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। इसके बाद अमेरिका ने इस वर्ष 24 फरवरी से 150 दिन के लिए व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत सभी आयात पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगा दिया। साथ ही, उसने धारा 301 के तहत प्रमुख निर्यातकों के खिलाफ उनकी

अतिरिक्त उत्पादन क्षमता एवं श्रम मानकों को लेकर दो जांच भी शुरू की। धारा 122 के तहत अधिकतम 150 दिन के लिए 15 प्रतिशत तक शुल्क लगाया जा सकता है। वहीं धारा 301 के तहत जांच में यदि यह पाया जाता है कि व्यापारिक साझेदारों के कदम अमेरिकी हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो शुल्क पर कोई सीमा नहीं होती। भारत ने दोनों जांच पर अपना जवाब दे दिया है और दोनों पक्षों के बीच परामर्श जारी है। गोयल ने एक कार्यक्रम में कहा कि कई बड़ी अमेरिकी कंपनियों ने भारत में निवेश की घोषणा की है क्योंकि देश, दुनिया के लिए एक पसंदीदा निवेश गंतव्य बना हुआ है। उन्होंने कहा, 'पिछले छह महीनों में अगर मैं अमेरिकी उद्योग से मिली विभिन्न निवेश प्रतिबद्धताओं को देखूँ, तो यह आंकड़ा संभवतः 60 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक होगा। अमेजन के डेटा केंद्र निवेश और गूगल के डेटा केंद्र निवेश को देखें। मेरी समझ यह है कि अमेरिका और भारत स्वाभाविक साझेदार की तरह काम कर रहे हैं।

मार्गति की कारें जून से 30,000 रुपये तक महंगी होंगी

नयी दिल्ली : देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मार्गति सुजुकी इंडिया बढ़ती मुद्रास्फीति और लागत में बढ़ोतरी के कारण जून, 2026 से अपने विभिन्न मॉडल की कीमतों में 30,000 रुपये तक की बढ़ोतरी करेगी। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि उसने अपने पूरे मॉडल पोर्टफोलियो में वाहनों की कीमतों में जून से 30,000 रुपये तक की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कंपनी ने कहा, 'पिछले कुछ महीनों से लागत में बढ़ोतरी के प्रभाव को कम करने के लिए कंपनी लागत कटौती उपायों के जरिये लगातार प्रयास कर रही है। कंपनी ने कहा कि मुद्रास्फीति का दबाव अब ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है और प्रतिकूल माहौल लगातार बना हुआ है। ऐसे में बढ़ी हुई लागत का एक हिस्सा बाजार पर डालना आवश्यक हो गया है, जबकि ग्राहकों पर इसका प्रभाव न्यूनतम रखने का प्रयास जारी रहेगा। मार्गति सुजुकी इंडिया फिलहाल शुरुआती श्रेणी की मार्गति सुजुकी एस-प्रेसो से लेकर प्रीमियम यूटिलिटी इन्विकटो बेचती है।

न्यूज अपडेट
एलआईसी का चौथी तिमाही का मुनाफा 23 प्रतिशत बढ़कर 23,420 करोड़ रुपये

नयी दिल्ली : भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में शुद्ध लाभ 23 प्रतिशत बढ़कर 23,420 करोड़ रुपये रहा है। देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी ने वित्त वर्ष 2024-25 की समान तिमाही में 19,013 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया था। एलआईसी ने बहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी कुल आय बढ़कर 2,53,592 करोड़ रुपये हो गई, जो 2024-25 की समान अवधि में 2,22,805 करोड़ रुपये थी। वित्त वर्ष 2025-26 की जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी की पहले साल की प्रीमियम आय बढ़कर 12,970 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले की समान अवधि में 11,069 करोड़ रुपये थी। समीक्षाधीन अवधि में नवीकरण प्रीमियम से आय बढ़कर 81,933 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले यह 79,138 करोड़ रुपये थी। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में कंपनी का शुद्ध लाभ 19 प्रतिशत बढ़कर 57,419 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 में 48,151 करोड़ रुपये था। पूरे वित्त वर्ष के दौरान कंपनी की कुल आय बढ़कर 9,73,288 करोड़ रुपये रही, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 8,84,148 करोड़ रुपये थी। कंपनी के निदेशक मंडल ने 2025-26 के लिए 10 रुपये अंतिम मूल्य वाले प्रत्येक शेयर पर 10 रुपये के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है।

सोने 600 रुपये मजबूत, चांदी में 5,000 रुपये का उछाल

नयी दिल्ली : राष्ट्रीय राजधानी के सरफा बाजार में बहस्पतिवार को सोने की कीमत 600 रुपये बढ़कर 1.65 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई और चांदी भी 2.71 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। भू-राजनीतिक तनाव के बीच कारोबारी कीमती धातुओं को लेकर सतर्क रूप से आशावादी बने रहे। स्थानीय बाजार के जानकारों के अनुसार, लगातार तीसरे सत्र में बढ़त जारी रखते हुए, 99.9 प्रतिशत शुद्धता वाले सोने का भाव 600 रुपये बढ़कर 1,65,500 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया, जो बुधवार के बंद भाव 1,64,900 रुपये से अधिक है। इस कीमती धातु की कीमतों में पिछले तीन सत्रों में कुल 2,700 रुपये की बढ़त दर्ज की गई है। कारोबारियों ने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक स्तर पर महंगाई को लेकर चिंताओं ने अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल में मजबूती के बावजूद, इस धातु की खरीद को समर्थन दिया। बाजार के जानकारों के अनुसार, चांदी की कीमतों में भी सुधार देखने को मिला, और इसकी कीमत 5,000 रुपये उछलकर 2,71,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। इसे सस्ते भाव पर खरीदारी और औद्योगिक मांग में सुधार के रुख से मदद मिली। विश्लेषकों ने कहा कि अमेरिका-ईरान संघर्ष और हॉमरुज जलडमरूमध्य से जुड़ी बाधाओं को लेकर चिंताओं ने कीमती धातुओं की मांग को लगातार बनाए रखा और रुपये में कमजोरी ने भी स्थानीय कीमतों को समर्थन दिया। अंतरराष्ट्रीय बाजारों में गिरावट के बावजूद घरेलू सरफा कीमतें मजबूत बनीं रहीं। हाजिर सोने का भाव मामूली रूप से गिरकर 4,534.54 डॉलर प्रति औंस रह गया, जबकि चांदी लगभग एक प्रतिशत फिसलकर 75.39 डॉलर प्रति औंस रह गई।

'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम के लिए तीन ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल

नयी दिल्ली : 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम पर अधिकार हासिल करने के लिए तीन अलग-अलग ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल किए गए हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड से यह जानकारी मिली है। ये आवेदन ऐसे समय में दाखिल किए गए हैं जब एक व्यंग्य के रूप में शुरू किया गया राजनीतिक संगठन 'कॉकरोच जनता पार्टी' सोशल मीडिया पर टिप्पणियों और डिजिटल मौजूदगी के कारण कुछ ही दिनों में लाखों लोगों तक पहुंच बनाने और बड़ी संख्या में फॉलोअर्स जुटाने के कारण चर्चा में आया है। हालांकि, संगठन के सोशल मीडिया मंच 'एक्स' के खाते पर भारत में रोक लगा दी गई है, लेकिन ट्रेडमार्क पंजीकरण पोर्टल पर दाखिल आवेदनों में राजनीतिक और सामाजिक सेवाएं उपलब्ध करने की श्रेणी के तहत ट्रेडमार्क पंजीकरण की मांग की गई है।

उतार-चढ़ाव भरे कारोबार में सेंसेक्स 135 अंक टूटा, निफ्टी स्थिर

मुंबई : स्थानीय शेयर बाजारों में बहस्पतिवार को उतार-चढ़ाव भरे कारोबार के बीच शुरुआती बढ़त कायम नहीं रह सकी और दोनों प्रमुख सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए। प्रमुख कंपनियों के शेयरों में मुनाफावस्तु की दबाव से बीएसई सेंसेक्स 135.03 अंक टूटकर 75,183.36 अंक पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 4.30 अंक की मामूली गिरावट के साथ 23,654.70 अंक पर रहा। कारोबार के दौरान सेंसेक्स में करीब 949 अंकों का उतार-चढ़ाव देखा गया। सेंसेक्स की कंपनियों में बजाज फाइनेंस, टेक महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिस्को, इन्फोसिस और भारतीय एयरटेल के शेयर नुकसान में रहे। वहीं इंटरनेट एंजिन, टैट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और अदाणी पोर्ट्स में तेजी दर्ज की गई। विश्लेषकों के अनुसार सकारात्मक वैश्विक संकेतों के बावजूद ऊंचे स्तर पर बिकवाली और आर्थिक चिंताओं के कारण बाजार दबाव में रहा। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की लगातार बिकवाली, वैश्विक बॉन्ड प्रतिफल में वृद्धि और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों से निवेशकों में सतर्कता बनी हुई है। एशियाई बाजारों में जापान का निष्की और दक्षिण कोरिया का कॉर्पोरेट बजट में रहे, जबकि चीन और हांगकांग के बाजार गिरावट के साथ बंद हुए।



एसबीआई कर्मचारियों ने दी 25 मई से दो दिवसीय हड़ताल पर जाने की चेतावनी

नयी दिल्ली : भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारियों ने पर्याप्त कर्मियों की नियुक्ति सहित विभिन्न मांगों को लेकर 25 मई से दो दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल की चेतावनी दी है। एसबीआई के कर्मचारी यह हड़ताल अखिल भारतीय स्टेट बैंक कर्मचारी महासंघ (एआईएसबीआईएसएफ) के तहत करेंगे। यदि हड़ताल होती है, तो इससे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बैंकिंग कार्यों पर पांच दिनों तक असर पड़ेगा, क्योंकि हड़ताल की तारीख से पहले चौथा शनिवार और रविवार पड़ रहा है। इसके अलावा, हड़ताल समाप्त होने के एक दिन बाद, 27 मई को ईद अल-अजहा के कारण कई राज्यों में छुट्टी रहेगी। कर्मचारी महासंघ ने एक बयान में कहा कि मांगों में संदेशवाहकों, सशस्त्र गार्डों की नियुक्ति और एनपीएस कर्मचारियों के लिए पेंशन कोष प्रबंधक बदलने के विकल्प की मांग भी शामिल है।

फसल ऋण को किसानों के 'सिबिल स्कोर' से न जोड़ें बैंक : फडणवीस

मुंबई : महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बहस्पतिवार को बैंकों से कहा गया है कि वे किसानों के फसल ऋण की मंजूरी को उनके 'सिबिल' स्कोर से न जोड़ें। आगामी खरीफ फसल के मौसम की तैयारियों की समीक्षा के लिए हुई एक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने उन उर्वरक डीलर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी, जो किसानों को अतिरिक्त उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करते हैं। फडणवीस ने कहा, 'हर बैंक को, मुख्यतः से लेकर शाखा स्तर तक, यह बता दिया गया है कि फसल ऋण को 'सिबिल' की शर्तों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारियों ने भी इसकी पुष्टि की है। 'सिबिल' स्कोर से जुड़ी समस्याओं के कारण किसी भी किसान को परेशानी नहीं होनी चाहिए।' 'सिबिल' स्कोर का उपयोग वित्तीय संस्थानों द्वारा किसी व्यक्ति की ऋण पात्रता को आंकने के लिए किया जाता है। फडणवीस ने कहा कि बैंक के दौरान कृषि ऋण माफी और कृषि ऋण से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने



कहा कि सरकार जल्द ही घोषित कृषि ऋण माफी योजना को लागू करेगी, और कहा, 'हम इन कर्जों को माफ करेंगे। मंत्रिमंडल में पहले ही चर्चा हो चुकी है, और बाकी जिलों से आंकड़ों के आने के बाद, 30 जून से पहले ऋण माफी लागू कर दी जाएगी।' महाराष्ट्र में खरीफ की खेती का क्षेत्र लगभग 152 लाख हेक्टेयर है, जिसमें सोयाबीन और कपास का हिस्सा लगभग 88 लाख हेक्टेयर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संभावित रूप से कठिन मानसून के मौसम के लिए कम कर रही है। फडणवीस ने कहा कि प्राथमिक पूर्वानुमानों से पता चलता है कि जून से सितंबर तक वर्षा धीरे-धीरे कम हो सकती है।

श्री गणेशाय नमः

श्री हनुमंते नमः

ॐ नमः शिवाय

पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर लेकटाउन धाम में दशम बार श्री श्री १,२५,००० (सवा लाख) हनुमान चालीसा पाठ महायज्ञ का सामूहिक संगीतमय आयोजन (३१ पंडितों द्वारा)

शनिवार २३ मई से शनिवार १३ जून २०२६

ध्वजा शोभायात्रा : २३ मई, सुबह ७:३० बजे

पूर्णाहुति : शनिवार १३ जून २०२६

मंदिर प्रांगण से आरम्भ होकर बांगुड एवेन्यू, जैशोर रोड, लेकटाउन होते हुए पुनः मंदिर पहुंचेगी।

सुंदरकाण्ड पाठ, हवन, भंडारा एवं भजन संध्या

स्थान :- श्री बाल हनुमान मंदिर, लेकटाउन धाम, कोलकाता

विशिष्ट अतिथि वृन्द

श्री दिलीप जी महाराज (भारत सेवाश्रम संघ)
डॉ. शारद्वत मुखर्जी (माननीय विधायक)
श्री पीयूष कानोडिया (माननीय विधायक)
श्री विजय ओझा (माननीय विधायक)
श्री मृगांक भट्टाचार्य (पूर्व पार्षद)

सहयोगी संस्थाएं

श्री बाल हनुमान महिला समिति
अखिल भारतीय गौड़ ब्राह्मण सभा
श्रीभूमि संसद
श्रीभूमि विकास मंच
बांगुड एवेन्यू संघ
बांगुड जागरण मंच
भारतीय संस्कृति संवर्द्धन समिति
पूर्व कलकत्ता नागरिक परिषद
श्री मैडू क्षत्रिय स्वर्णकार महिला समिति

विशिष्ट शुभेच्छु वृन्द

पद्मश्री श्री प्रह्लाद राय अग्रवाला
श्री बिस्वनाथ सेकसरिया
श्री प्रदीप सराफ
श्री अमित गोयल
श्री किशन मिररानिया अग्रवाल
श्री राजेश चिड़ीमार
श्री कालीचरण अग्रवाल
श्री ओम जालान
श्री बनवारीलाल सोती
श्री जगदीश प्रसाद जाजू
श्री बैजनाथ मिश्र
श्री विरम प्रकाश सुल्तानिया
श्री द्वारिका आयुष टेकड़ीवाल
श्री शंकरलाल कारीवाल
श्री लक्खी प्रसाद पसारी
श्री प्रेम कुमार अग्रवाल
श्री महावीर प्रसाद दमानी (प्रोस्पेरा फाइनेंसियल सोल्युशंस)
श्री हरी प्रसाद बुधिया
श्री ललित बेरीवाल
श्री निकुंज बेरीवाल
श्री त्रिलोक कोठारी
श्री श्रेयांश सुराणा
श्री मनोज गुप्ता
श्री प्रमोद अग्रवाल
श्री पवन मूंधड़ा
श्री संजय बगड़िया
श्री बिजय डोकानिया
श्रीमती मंजु डागा
श्री मोंटी अग्रवाल
श्री विद्यासागर मंत्री
श्री सुभाष मुरारका
श्री सुधीर भट्टाचार्य
श्री सीताराम गोयल
श्री बाबूलाल बंका
श्री सुब्रत दास
श्री जुगल सरिया
श्री सुशील ओझा
श्री अनिल गोयल
श्री अशोक अग्रवाल
श्री उत्तम अग्रवाल
श्री दीपू शर्मा
श्री अनूप गाड़ोदिया
श्री गोपाल अग्रवाल
श्री विकास अग्रवाल
श्री गोपाल जैन
श्री लक्ष्मण अग्रवाल
श्री विनोद जाजू
श्री गोविन्द कल्लोया
श्री संजय कंसल
श्री पिंटू सुल्तानिया
श्री सुभम बगड़िया
श्री सतीश तापडिया
श्री पवन गोयनकर
श्री अशोक कुमार जैन
श्री शिव चोधरी
श्री संदीप गुप्ता

आयोजन एवं व्यवस्था समिति

श्री हरि किशन राठी (चेयरमैन)
सुधीर शर्मा
संदीप अग्रवाल
अमित कुमार धानुका
दीपक सोमानी
प्रकाश चंडालिया
अनूप जोशी
प्रवीण मिश्र
सुदर्शन गाड़िया
दीनदयाल जोशी
गगन कडेल
नरेंद्र कुमार गोयल
ओम प्रकाश चौधरी
अरुण शर्मा
अविनाश शर्मा
मनोज कुमार अग्रवाल
सुनील तोषावर
दयाराम कडेल
गणेश शर्मा
डॉ. आर. के. पोद्दार
नरेश सांगानेरिया
विवेक सांगानेरिया
राजेश अग्रवाल
गोपाल कानोडिया
मनमोहन अग्रवाल
प्रवीण चौधरी
संजय गुप्ता
गंगा प्रसाद चौधरी
प्रमोद बगड़िया
मनोज बजाज
श्यामसुंदर मंत्री
प्रणय अग्रवाल
गोपाल बंका
प्रकाश शर्मा
दुष्यंत केडिया
संजय बगड़िया
दीपक बजाज
राकेश चंडालिया
पंकज केशान
अरुण गोयनका
संजय अग्रवाल
पंकज केशान
राज कुमार टिबडेवाल
मनोहरलाल अग्रवाल
बालकृष्ण सराफ
कौशल अग्रवाल
राकेश जैन
श्री गाड़ोदिया
प्रशांत सोनी
आदित्य अग्रवाल
रोहित केडिया
महेश भुवावका
विजय डिडियाल

दिव्य शुभारम्भ कल

स्व. दिलीप कुमार अग्रवाल

FOLLOW US

प्रसारण

35

श्री बाल हनुमान (लाल बाबाजी) सेवा ट्रस्ट
358, लेकटाउन ब्लॉक-ए, कोलकाता - 700089. फोन : 033-25346931

वर्ष 11, पूर्णांक 3599 अंक 065 RNI No WBHN/2016/66788, सर्वांग प्रकाशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सरोज राय द्वारा रजि. 17, बालमुकुन्द मन्कर रोड, 2सरा तल्ला, कोलकाता-700 007 से प्रकाशित। एल. एस. पब्लिकेशन्स प्रा. लि. 4, कैनेल वेस्ट रोड, कोलकाता-700 015 से मुद्रित। सम्पादक- अनिल कुमार राय (पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी), कॉर्पोरेट आफिस : 230, चित्तरंजन एवेन्यू, कोलकाता-700 006, विज्ञापन एवं प्रसार-9874555256/7044444522, ई-मेल news@samagya.in